● वर्ष-4
● अंक-178
रायपुर, गुरुवार
06 मार्च 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» करियर में मददगार होंगे....

दिल्ली में पकड़ी गई महिला नक्सली

नाम के साथ बदला पता, झारखंड में ली हथियारों की ट्रेनिंग

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली में पहचान बदलकर रह रही नक्सली महिला को गिरफ्तार किया है। उसने नाम व पहचान बदल ली थी। वह नक्सली बनने के समय पांच साल का कठोर प्रशिक्षण लिया था। गिरफ्तार नक्सली महिला वर्ष 2018, 2019 और 2020 में तीन मुठभेड़ों में शामिल रही थी।

23 साल की है महिला नक्सली: अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि गिरफ्तार महिला (23 वर्ष) झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुदाबुरू गांव की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर लिछमन और एसआई देवेंद्र को एक माओवादी चरमपंथी महिला के बारे में 4 मार्च को गोपनीय जानकारी मिली,जो सीपीआई माओवादी नक्सली समूह का सदस्य है। नाम और पता बदल कर रह रही थी दिल्ली में यह पता चला कि नक्सली महिला अपनी असली पहचान छिपाकर और गलत नाम का इस्तेमाल कर दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में रह रही है। वह वर्तमान में महाराणा प्रताप एन्क्लेव, पीतमपुरा में भी नौकरी करती है। पुलिस टीम ने महाराणा प्रताप एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली में छापेमारी कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया।

नक्सल कैंप में ले चुकी है प्रशिक्षण: गिरफ्तार महिला एक किसान परिवार से है और उसके तीन भाई और दो बहनें हैं। उसके गांव का एक माओवादी उसके पास आया और उसे बेहतर भोजन, देखभाल और सुरक्षा का लालच देकर अपने साथ ले गया। उस समय नक्सली शिविर में 300-450 लोग रहते थे, जिनमें 40-50 महिलाएं थीं। उसकी उम्र के 4-5 बच्चे शिविर में शामिल थे।

नक्सल गतिविधियों में उसकी भागीदारी बेहद कम उम्र यानी 10 वर्ष की आयु से शुरू हुई जब वह कुख्यात नक्सली शिविर भाकपा माओवादी उग्रवादी जीवन कंडुलना में शामिल हुई।

ज्ञान से गति की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़

वर्ष 2025-26 का बजट समावेशी विकास की ओर छत्तीसगढ़ सरकार का एक और कदम,वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, वित मंत्री ने विधानसभा बजट 2025-26 सामान्य चर्चा पर दिया जवाब

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने विधानसभा बजट 2025-26 सामान्य चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना महत्वाकांक्षी बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 का एक लाख 65 हजार करोड़ रूपए का बजट वर्ष 2024-25 के बजट एक लाख 47 हजार 500 करोड़ रूपए से 12 प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष का बजट GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित था, जबकि इस वर्ष का बजट GATI (गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर केन्द्रित है। यह राज्य का अब तक सबसे बड़ा बजट है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि इस बजट से विकास एवं जनकल्याण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह बजट राज्य को तेजी से विकास के पथ पर ले जाने और 2030 के लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने का संकल्प है। यह नवाचार, अधोसंरचना और समावेशी विकास को प्राथमिकता देने वाला बजट है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह बजट राज्य के रजत जयंती वर्ष का बजट है। यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है।

प्रस्तुत बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 12 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है. जो वर्ष 2025-26 में 6,35,918 करोड़ रूपए तक होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय में 9 प्रतिशत वृद्धि, बिना नया कर लगाए, राजस्व में 11 प्रतिशत वृद्धि तथा राजस्व अधिशेष 2,804 करोड़ रूपए रहने का अनुमान है। राज्य का पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ रूपए प्रस्तावित है, जो अब तक का सर्वाधिक है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार ने अपने बजट में व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से कर के बोझ को कम करने के लिए ई-वे बिल सीमा 50 हजार रूपए से बढ़ाकर एक लाख रूपए की है। नए बजट में 25 हजार रूपए तक की वैट देनदारी को माफ किया गया है, जिससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को राहत मिलेगी। अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टांप शुल्क उपकर हटा दिया गया है।

वर्ष 2025-26 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने कई प्रमुख घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी बजट प्रावधान किया है, जिसमें कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8500 करोड़, महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 4500 करोड़, पांच एचपी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रूपए सहित अन्य योजनाओं को पूरा करने के लिए भी बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले साल के बजट से 300 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री मोबाईल टॉवर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, 500 नई सहकारी समितियों का गठन का प्रावधान किए जाने के साथ ही केन्द्र सरकार की पीएसएस योजना के तहत पहली बार दलहन और तिलहन की खरीदी के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के साथ ही जशपुर जिले के कुनकुरी में नया मेडिकल कॉलेज खोलने तथा रिक्त सरकारी पदों को तेजी से भरने का भी प्रावधान है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल की बजट में उद्योग विभाग को तीन गुना अधिक राशि आबंटित की गई है।वर्ष 2025-26 के बजट में 10 नवीन योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मुख्यमंत्री बायपास एवं रिंग रोड निर्माण योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप, सियान केयर योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अटल सिंचाई योजना, छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति तथा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के साथ छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश प्रशिक्षण योजना शामिल है।

श्री चौधरी ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार किसानों को तड़पा-तड़पा कर किस्तों में भुगतान करती थी, जबकि हमारी सरकार ने पिछले वर्ष 13,320 करोड़ रूपए और इस साल 12 हजार करोड़ रूपए का एकमुश्त भुगतान किसानों को किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य की ऋण स्थिति को सुरक्षित बताते हुए कहा कि कुल ग्रॉस लोन से स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस और जीएसटी लोन को घटाने के बाद राज्य का ऋण अनुपात 19 प्रतिशत है, जो 25 प्रतिशत की सीमा से काफी सुरक्षित है। श्री चौधरी ने बताया कि जहां हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में 42-45 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार अपने कर्मचारियों को 53 प्रतिशत डीए प्रदान कर रही है, जो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में कुम्हारी नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण संपन्न।

बंगलूरू में संघ की सर्वोच्च बैठक, मोहन भागवत भी होंगे शामिल

नइादल्ला। कद्र म सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल काफी समय पहले ही बीत चुका है और नए भाजपा अध्यक्ष के चुने जाने की प्रक्रिया चल रही है। चर्चा है कि बहुत जल्द भाजपा को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। इन्हीं चर्चाओं के बीच भाजपा के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय %अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा% की तीन दिवसीय बैठक (21-23 मार्च) को बंगलूरू में होना निश्चित किया गया है। इस बैठक में संघ के सर्वोच्च पदाधिकारी मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले और सभी सहयोगी संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री

सहित 1480 कार्यकर्ता शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा है कि संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की इस वर्ष की बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में संघ के पिछले वर्ष के कार्यों की समीक्षा की जाती है। और अगले वर्ष के लिए नए लक्ष्य तय किए जाते हैं। संघ की कार्य पद्धति में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा निर्णय करने वाली सर्वोच्च इकाई है। इस बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष होता है।

दरअसल, इस साल आने वाली विजयादशमी (दशहरा) 2025 को संघ के सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं। आरएसएस इस विजयादशमी से लेकर अगले वर्ष की विजयादशमी को अपने शताब्दी वर्ष के तौर पर देखेगा और इस बीच संघ के कार्यों को विस्तार देने के लिए इस बैठक में योजना बनाई जाएगी। आरएसएस का लक्ष्य है कि वह जल्द से जल्द देश के हर ब्लॉक स्तर तक पहुंचे। इस लक्ष्य को लेकर भी इस बैठक में निर्णय किए जा सकते हैं।

संघ के सबसे बड़े लक्ष्य

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस समय पंच परिवर्तन के माध्यम से देश में एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर चुका है। इसके अंतर्गत लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, नागरिक कर्तव्यों का बोध बढ़ाने, सामाजिक समरसता बनाए रखने और प्लास्टिक का उपयोग न करने को लेकर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। भाजपा कुटुंब प्रबोधन के जरिए सनातनी परिवारों को अपने मूल संस्कारों को अपने जीवन में अपनाने की बात भी कही जा रही है। बैठक में इन पंच परिवर्तन के प्रयासों पर विशेष चर्चा की अपेक्षा है।

प्रमुख समाचार

नेशनल कॉर्डिनेटर आनंद कुमार को मायावती ने हटाया

सहारनपुर। जेजेपुरम निवासी रणधीर सिंह बेनीवाल को बहुजन समाज पार्टी में नेशनल कोर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिली है। पार्टी सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कॉर्डिनेटर पद से हटाते हुए रणधीर बेनीवाल पर भरोसा जताया है। इससे जनपद के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। रणधीर बेनीवाल नगर पालिका सहारनपुर में सभासद भी रहे हैं। उनकी पुत्रवधू पहले बोर्ड में पार्षद रहे हैं। वह शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी का झंडा थामे रहे। उन्हें 2014 में सहारनपुर जिला प्रभारी पद की जिम्मेदारी पार्टी ने दी थी। इसके बाद 2016 से 2018 तक वह सहारनपुर और मेरठ मंडल के भाईचारा कमेटी के मंडल प्रभारी रहे। जून 2018 से वह हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ के प्रभारी हैं, जो लगातार इन राज्यों में पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहे। रणधीर बेनीवाल शांत स्वभाव के अनुशासित नेता माने जाते हैं। यही वजह है कि पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने भाई आनंद के बाद उन पर भरोसा जताते हुए नेशनल कॉर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी सौंपी है। उनको

कुछ अंग्रेजी को अपनाते हैं, हिंदी को मान्यता नहीं देते-हिमंत

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को किसी का नाम लिए बिना कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग अंग्रेजी को अपनाते हैं, लेकिन वे हिंदी को समान मान्यता नहीं देते। यहां क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हिंदी को न केवल भारत की आधिकारिक भाषा, बल्कि सभी भारतीयों के दिलों में गूंजने वाली एक भाषा है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत में इस समय हिंदी को लेकर वहां के मुख्यमंत्री काफी बवाल कर रहे हैं। उन्होंने हिंदी को एकता की शक्ति के रूप में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए राजभाषा सम्मेलन में मुख्यमंत्री सरमा ने सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में क्षेत्रीय भाषाओं की अहम भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने लोगों से भारत की स्वदेशी भाषाओं पर गर्व करनेका आह्वान करते हुए यह भी बताया कि हिंदी सीखने से रोजगार और व्यापार के अवसरों में विस्तार होता है। हिमंता ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग अंग्रेजी को अपनाते हैं, लेकिन वे हिंदी को समान मान्यता नहीं देते।

राजीव गांधी को पीएम कैसे बनाया गया? : मणिशंकर

नई दिल्ली। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बुधवार को अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मणि शंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शिक्षा को लेकर सवाल उठाए है। इस वीडियो में मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि राजीव गांधी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी असफलता का सामना करना पड़ा, जबकि वहां पास होना आसान माना जाता है। इसके बाद वह इंपीरियल कॉलेज, लंदन गए, लेकिन वहां भी वह सफल नहीं हो सके। मणिशंकर अय्यर ने यह भी सवाल किया कि इतने कमजोर शैक्षिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री कैसे बनाया गया। हालांकि, राजीव गांधी की शैक्षिक कठिनाइयों ने उन्हें राजनीति में आने से नहीं रोका। 1984 में अपनी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वह भारत के प्रधानमंत्री बने थे। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, %(अमित) मालवीय को चीजों को एडिट करने की आदत है। इसमें कितना सही है और कितना गलत, यह तो मणिशंकर ही बता सकते हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि राजीव गांधी पास हुए या फेल।

हमारी सरकार बनी तो 100% डोमिसाइल : तेजस्वी

पटना। बिहार में राजनीतिक तापमान एक बार फिर बढ़ गया है। युवा राजद बिहार के बैनर तले पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में 'युवा चौपाल' कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने युवा नीति और रोजगार पर बड़े एलान किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद प्रदेश युवा अध्यक्ष राजेश यादव ने की, जबकि संचालन प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी युवा राजद बिहार शिवेंद्र कुमार तांती ने किया। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि अगर राजद सरकार में आती है, तो प्रदेश की नौकरियों में 100% डोमिसाइल लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। हम बिहार सरकार की नौकरियों में आवेदन शुल्क माफ करेंगे और एक महीने के अंदर युवा आयोग का गठन करेंगे। उन्होंने महिलाओं के लिए 'माई-बहन मान योजना' की भी घोषणा की, जिसके तहत बिहार की सभी माताओं और बहनों को 2500 प्रतिमाह दिया जाएगा। साथ ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली, दिव्यांग पेंशन और वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 1500 किया जाएगा।

जयशंकर ने ब्रिटेन व्यापार समझौते पर की चर्चा

लंदन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ब्रिटिश समकक्ष डेविड लैमी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने भारत-ब्रिटेन संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। इस बातचीत में व्यापार समझौते, रणनीतिक सहयोग और राजनीतिक संबंध शामिल थे। यह बैठक केंट में स्थित शेवेनिंग हाउस में दो दिनों तक चली। लैमी ने जयशंकर की मेजबानी की। दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन संघर्ष सहित कई वैश्विक मुद्दों पर भी सलाह-मशविरा किया। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में दोनों नेताओं को ऐतिहासिक 17वीं सदी के शेवेनिंग हाउस का दौरा करते और उसके बगीचों में टहलते हुए गहन बातचीत में मशगूल देखा गया। इस मुलाकात और बातचीत के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि बातचीत व्यापक और उत्पादक रही। इसके अलावा, उन्होंने यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया, बांग्लादेश और कॉमनवेल्थ जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बात की। जयशंकर ने कहा कि आज की अस्थिर दुनिया में भारत-यूके संबंध स्थिरता और समृद्धि लाने में योगदान देते हैं।

औरंगजेब को आदर्श मानने वाले को यूपी भेजिए, इलाज कर देंगे : योगी

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के बजट सत्र में विधान परिषद को संबोधित करते हुए महाकुंभ के आयोजन का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि यह ऐसा आयोजन था जिसे लंबे समय तक दुनिया याद रखेगी। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां इससे सहमत नहीं थीं और महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार किया फिर भी लोगों की आस्था नहीं डिगी।

उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। जो लोग संघ की विचारधारा से नहीं जुड़े हैं वो भी महाकुंभ के आयोजन की प्रशंसा कर रहे हैं। 45 दिन तक चले आयोजन में कोई लूट की घटना नहीं हुई। कोई अपहरण की घटना नहीं हुई। यह सनातन के सामाजिक अनुशासन का प्रभाव है। जो कि कहता है कि पूरा देश एक है और यहां जातिवाद और क्षेत्रवाद की कोई जगह नहीं है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये उन लोगों को जवाब है जो कि जल के प्रदूषण और अन्य तमाम छोटी खबरों को लेकर आयोजन पर सवाल उठा रहे थे और दुष्प्रचार कर रहे थे। देश की जनता के लिए गंगा सबसे पवित्र है और विज्ञान कहता है कि बहता हुआ जल खुद को पवित्र करता रहता है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि महाकुंभ में जैसी जिसकी दृष्टि थी वैसा ही उसने वहां देखा। सनातन के मानने वालों के लिए महाकुंभ एक गर्व का विषय है जो कि पूरी दुनिया को एकता का संदेश देता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था को आजीविका से जोड़ा है। यही कारण है कि प्रयागराज का एक नाविक परिवार जिसके पास 130 नावें थीं। उन्होंने पूरे आयोजन के दौरान 30 करोड़ रुपये की कमाई की। महाकुंभ का वृहद आर्थिक पक्ष है। हमारा अनुमान है कि इस आयोजन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को साढ़े तीन लाख करोड़ का लाभ हुआ है।

औरंगजेब सपा के नायक

मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि सपा के लोगों के लिए औरंगजेब गर्व का विषय है जिसने

अपने पिता को कैद कर उन्हें पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसा दिया था। उन्होंने कहा कि सपा का अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने अबू आजमी का नाम लिए बिना कहा कि सपा को उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा को उस नेता के बयान का खंडन करना चाहिए और पार्टी से निकाल देना चाहिए। नहीं तो उसे यहां बुलाइये। हम उसका इलाज कर देंगे। यूपी ऐसे लोगों का उपचार अच्छे से करता है। ये लोग महाकुंभ को कोसते हैं और औरंगजेब पर गर्व करते हैं। उसे यूपी भेज दीजिए हम इलाज कर देंगे। बता दें कि अबू आजमी ने बयान दिया था कि वह औरंगजेब पर गर्व करते हैं।

अबू को जेल भेजा जाएगा-फडणवीस

महाराष्ट्र विधानसभा में सपा विधायक अबू आजमी को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें %100 प्रतिशत% जेल भेजा जाएगा। यह टिप्पणी सीएम फडणवीस ने विधान परिषद में की, जब उनसे विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा। अबू आजमी को उनकी टिप्पणी के कारण विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब की सराहना की थी। सपा विधायक ने औरंगजेब के शासन के दौरान भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा (म्यांमार) तक पहुंचने का दावा किया था और कहा था कि उस समय भारत की जीडीपी 24 प्रतिशत थी। इसके साथ ही, उन्होंने औरंगजेब और मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के बीच संघर्ष को एक %राजनीतिक संघर्ष% बताया था।इस टिप्पणी के बाद, विधानसभा में अबू आजमी के खिलाफ जमकर विरोध हुआ और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उनकी निलंबन की मांग की। शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों के खिलाफ कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और सरकार को इस तरह की टिप्पणियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठाकरे ने यह भी मांग की कि आजमी को विधानसभा से स्थायी रूप से निलंबित किया जाए।

वहीं अबू आजमी ने अपनी विवादित टिप्पणी के बाद कहा कि उन्होंने यह बयान विधानसभा के बाहर दिया था, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया था ताकि सदन में कामकाजी माहौल बना रहे।

नक्सलगढ़ में माओवादियों के टीसीओसी से निपटने के लिए फोर्स तैयार, बस्तर में अलर्ट

बस्तर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में गर्मी के दिनों में अक्सर बड़ी नक्सली घटनाएं होती है। इसका कारण है कि हर साल मार्च से जून के बीच बस्तर में माओवादी संगठन टीसीओसी कैंपेन टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं। इस कैंपेन के तहत 4 महीने खासकर गर्मी के सीजन के दौरान नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं।

टीसीओसी यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। गर्मी शुरू होते ही बस्तर में नक्सली संगठनों का टीसीओसी कैंपेन शुरू होता है। मार्च से जून के बीच होने वाले इस कैंपेन में माओवादी संगठन सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान पहुंचाने बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। इसके साथ ही सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को भी आग के हवाले किया जाता है।

टीसीओसी के दौरान बस्तर में बीते सालों में कई बड़ी नक्सली घटनाएं हुई। जिनमें जवानों को काफी नुकसान हुआ। 3 अप्रैल 2021 को सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में टेकलगुड़ा में नक्सली घटना में 22 जवान शहीद। 21 मार्च 2020 में सुकमा जिले के मीनपा में माओवादी घटना में 17 जवान शहीद। अप्रैल 2017 में सुकमा जिले के बुर्कापाल में नक्सली घटना में 25 जवान शहीद।

बस्तर आईजी का दावा है कि पहले के सालों में

नक्सली घटनाओं में जवानों को नुकसान हुआ है लेकिन बीते दो साल, साल 2024 और साल 2023 में सुरक्षा बलों की टाइट सिक्योरिटी की वजह से टीसीओसी के दौरान नक्सली किसी भी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सके। इस दौरान बस्तर संभाग के सातों नक्सल प्रभावित जिलों में कोई भी बड़ी नक्सली घटना नहीं हुई बल्कि इन दो सालों में नक्सल संगठन को बड़ा नुकसान पहुंचा है।

साल 2024 में सुरक्षाबलों के ऑपरेशन से नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। 15 अप्रैल 2024 में जवानों ने कांकेर जिले के छोटे बेठिया में एक एनकाउंटर को अंजाम दिया। इस एनकाउंटर में 29 माओवादी मारे गए। 4 अक्टूबर 2024 को नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले के थुलथुली में एनकाउंटर में 38 माओवादियों को जवानों ने मार गिराया।

वर्ष 2024 में सुरक्षाबलों ने 217 माओवादियों को मार गिराया। 2023 में 22 मुठभेड़ों में चार हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराने में सुरक्षाबल के जवानों को कामयाबी मिली। पुलिस ने बीते 2023 में 150 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। जबकि 78 माओवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। ना सिर्फ 2024 और 2023 में बल्कि इस साल की शुरुआत में भी नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। 9 फरवरी 2025 को बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व इलाके के अन्नापुर एनकाउंटर में जवानों ने 31 माओवादियों को मार गिराया।

बीते दो साल नक्सलियों को भले ही नुकसान हुआ हो लेकिन साल 2025 में नक्सलियों के टीसीओसी को देखते हुए फोर्स अलर्ट पर है। माओवादियों से निपटने के लिए सुरक्षाबलों ने रणनीति बना ली है। सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है। आईजी ने बताया कि गर्मियों के दिनों में बस्तर में टीसीओसी के दौरान माओवादी अक्सर बड़ी घटनाओं को अंजाम देते आये हैं। साल 2025 में अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसे देखते हुए बस्तर में अलर्ट जारी किया गया है। तमाम उपकरणों के साथ पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। बस्तर के सभी नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षाबल सतर्कता बरत रहे हैं।

शराब पीकर स्कूल आने वाला शिक्षक निलंबित

सरगुजा। शराब के नशे में स्कूल आने और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले शिक्षक एलबी शैलेंद्र सिंह पोर्ते के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। यह मामला गुमगरा खुर्द बरती पारा प्राथमिक शाला का है।

जानकारी के अनुसार, सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम गुमगरा खुर्द बरती पारा के प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक शैलेंद्र सिंह पोर्ते पर लगातार शराब के नशे में स्कूल आने और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप थे। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं 24 फरवरी को शिक्षक फिर शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा। ग्रामीणों की सूचना पर संकुल समन्वयक विनोद गुप्ता जांच के लिए स्कूल पहुंचे, जहां शिक्षक को नशे की हालत में पाया गया।

बिलासपुर में पटवारी पर रिश्वत का आरोप

अधिकारी से शिकायत

बिलासपुर। रतनपुर तहसील के पचरा गांव में पटवारी पर 60 हजार रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। पटवारी का 30 हजार रुपए रिश्वत लेते एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस मामले की शिकायत भी की गई है।

प्रार्थी केवल दास मानिकपुरी ने अनुविभागीय अधिकारी को लिखित शिकायत दी है कि पटवारी ने पट्टे की भूमि को ऑनलाइन दर्ज करने और ऋण पुस्तिका जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी। प्रार्थी ने शिकायत में बताया है कि पटवारी ने 60 हजार रुपए की रिश्वत मांगी, जिसके बाद दस प्रतिशत कर्जे में लेकर तीस हजार रुपए नगद दिया।

इस केस में पीड़ित ने पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रार्थी ने लिखित शिकायत में यह भी कहा है कि रकम देने के बाद भी जमीन की ऑनलाइन एंट्री नहीं हुई। इतना ही नहीं उसके बाद ना ही ऋण

पुस्तिका जारी की गई। शिकायत में यह भी लिखा है कि उसके पास पटवारी को रकम देने की वीडियो क्लिप उपलब्ध है। अब प्रार्थी ने पटवारी पर कार्रवाई करने और अपने तीस हजार रुपए वापस दिलवाने की मांग की है।

रतनपुर इलाके के एसडीओपी से इस पूरे प्रकरण की शिकायत हुई है। शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। किसान की शिकायत की जांच को लेकर जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है। यह देखने वाली बात होगी। जिला प्रशासन ऐसे केसों में अब तक गंभीर कार्रवाई करता आया है। इस केस में भी शिकायत के बाद बिलासपुर जिला प्रशासन एक्शन उठा सकता है।

सिविल सर्जन के खिलाफ प्रदर्शन

■ डॉक्टर, नर्सों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप, कलेक्टर से की शिकायत

जांजगीर चापा। जांजगीर चांपा जिले के जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर दीपक जसवाल पर डॉक्टरों और नर्सों ने मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। वही सिविल सर्जन के खिलाफ नारेबाजी कर रैली के माध्यम से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर आकाश छिकारा से शिकायत दर्ज कराई है।

सीनियर नर्स सा बोस ने कहा कि केजवाल्टी वार्ड पर ड्यूटी पर थी उस समय सिविल सर्जन डॉक्टर दीपक जसवाल पहुंचे कहा कि सिस्टर आप की नेता गिरी नहीं चलेगी मैं तुम्हे निपटा दूंगा ट्रांसफर कर दूंगा। मेरा कोई कुछ बिगड़ नहीं सकता मेरा स्वास्थ्य मंत्री रिश्तेदार है कलेक्टर मेरा दोस्त है हर मीटिंग में भी यही बात करता है और सीआर खराब करने की भी धमकी देता है। वही हर चीज में पवार दिखाता है। हम काम करते है फिर भी प्रेशर देता है काम वही हो रहा है।

एक जूनियर डॉक्टर को सिविल सर्जन का प्रभार दिया गया है। अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हैजिला अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के बजाय उन्होंने सिनियर डाक्टरों को डोमिनेट करना शुरू कर दिया ,स्टाफ नर्सों से बदसलूकी करते है और सभी लोगों को स्वास्थ्य मंत्री का भतीजा होने और कलेक्टर का दोस्त होने का धौंस जमाते हैं साथ स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर से गहरा संबंध होने का हवाला देते है और अपनी गलतियों को छुपाने के

लिए बाहरी रंग रोगन और सजावट कर अच्छी सुविधा होने का दावा करते है, जबकि डॉक्टर और स्टाफ में आक्रोश पहन रहा हैं स्थिति अभी नहीं सुधरेगी तो स्थिती और बिगड़ सकती है।

दीपक जायसवाल सिविल सर्जन ने बताया कि पूर्व में जिला अस्पताल की स्थिति बिगड़ी हुई थी ,जिसे सुधारने के लिए प्रयास किया गया जिसके परिणाम स्वरूप आज जिला अस्पताल में मरीजों को पर्याप्त सुविधा मुहैय्या कराई जा रही है ,अब दिन रात डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल में उपलब्ध रहते है ,उन्होंने कहा कि स्टाफ नर्स और किसी भी चिकित्सक से दुर्व्यवहार नहीं किया जाता प्रशासनिक कसावट के लिए दिशा निर्देश दिए जाते है।

कलेक्टर आकाश छिकारा ने कहा कि इस मामले में चिकित्सकों की शिकायत मिली है ,पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिला पंचायत गरियाबंद में भाजपा का कब्जा

पहली बार निर्वाचित जनपद सदस्य गौरी शंकर बने अध्यक्ष, लालिमा ठाकुर उपाध्यक्ष

गरियाबंद। जिला पंचायत सदस्य के कुल 11 सीटों में से 8 सदस्यों के साथ पहली बार पूर्ण बहुमत बनाने वाली भाजपा का गरियाबंद जिला पंचायत पर भी अब पूरी कंट्रोल होगी। भाजपा समर्थित गौरी शंकर कश्यप निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, वहीं लालिमा ठाकुर उपाध्यक्ष चुनी गईं हैं। अध्यक्ष का पद एसी केटेगिरी के लिए आरक्षित था। इस वर्ग से चुनाव जीत कर जिला पंचायत सदस्य बनने वाले दोनों सदस्य भाजपा के ही थे। बावजूद उसके नाम फाइनल करने में संगठन में जम कर माथा पच्ची हुई।

बिंद्रा नवागढ़ को मिला युवा नेतृत्व

बिंद्रा नवागढ़ विधान सभा क्षेत्र में चुने गए बड़े जनप्रतिनिधि नहीं थे ।जो है उनकी बात सरकार कम सुन रही है, ऐसे में क्षेत्रीय समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने बिन्द्रानवागढ़ विधान सभा क्षेत्र को सत्तासीन संगठन की ओर से एक मजबूत कंधा मिल गया है।

संघ की विलुप्त मोर्चा बंदी से मिली सफलता

32 साल का युवा गौरी शंकर संघ से जुड़ा हुआ है,विहिप के कई दायित्व का

निर्वहन कर रहा था देवभोग के गोहकेला ग्राम में जन्मे गौरी के पिता कृषक व भाई व्यापारी है ।ममेरा गांव मैनपुर ब्लॉक का सरगीगुड़ा है,बचपन इसी गांव में बीता था ।लिहाजा सरगीगुड़ा सीट में आसानी से जीत दर्ज कर लिया। मध्यम वर्गीय परिवार के इस होनहार युवक ने अपने कार्य क्षमता का परिचय दिया था,लिहाजा संघ व विहिप ने गौरी को अधिकृत प्रत्याशी बनाने से लेकर अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाने अहम भूमिका निभाया है। भाजपा का बहुमत का आंकड़ा इन्हीं दोनों नाम पर शुरू से सहमत थे,लेकिन जिम्मेदार नए नाम थोप रहे थे। नाम तय होने से पहले सदस्यों से सांसद रूपकुमारी चौधरी और राजिम विधायक रोहित साहू ने वन टू वन किया। इस चर्चा के बाद सदस्यों के सुझाए नाम पर संगठन की सहमति बन पाई।

गौरी शंकर कश्यप पद की गरिमा के अनुरूप कुर्सी के साथ न्याय करूंगा। सरकार की जन कल्याण कारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में जिला पंचायत की भूमिका हमेशा से अग्रणी रहे। इसी भाव विचार को लेकर अनुभवी सदस्यों के मार्गदर्शन में विकास के लिए काम करेंगे।

दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों को बराबर वोट मिले

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनावों के नतीजे आ रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले में बेहद रोचक मुकाबला दिखा। यहां भाजपा से नंदलाल मुड़ामी और कांग्रेस की तुलिका कर्मा के बीच रोचक और कड़ा मुकाबला हुआ। यहां 5 सीटों पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस और 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों का कब्जा है।

यहां बीजेपी के प्रत्याशी को 5 वोट मिले और कांग्रेस की प्रत्याशी को भी 5 वोट मिले। दोनों प्रत्याशियों को बराबर-बराबर वोट मिलने से मुकाबला रोचक हो गया। जिसके बाद दोनों प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ड्रॉ सिस्टम से निकालना पड़ा। ड्रॉ सिस्टम में भाजपा के प्रत्याशी नंदलाल मुड़ामी का भाग्य खुला और मुड़ामी की जीत हो गई। इस मुकाबले में कुछ देर तक दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों की सांसें अटकी रहीं। वहीं फैसला अपने पक्ष में आने के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है। इस जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद है। दंतेवाड़ा में भी बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर कामयाबी हासिल की है

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 नगर निगमों में जीत हासिल की थी। कांग्रेस को किसी भी नगर निगम में जीत हासिल नहीं हो पाई। उसके बाद बीजेपी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी जीत हासिल की है। नक्सलगढ़ की कई सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने निकाय चुनाव के साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सफलता हासिल की है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

शपथ पत्र दाखिल न किए जाने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बार काउंसिल में बीते छह वर्षों से चुनाव नहीं होने के मामले में हाईकोर्ट ने 18 फरवरी को दिए गए आदेश के अनुपालन की जानकारी मांगी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से शपथ पत्र दाखिल न किए जाने पर नाराजगी जताई। मामले में अगली सुनवाई आज 6 मार्च को होगी। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान पूर्व में मांगे गए हलफनामों की स्थिति जानी गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वकील ने बताया कि सचिव द्वारा शपथ पत्र डिस्पैच किया गया है, लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं हुई है। इस पर कोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया। इससे पहले 18 फरवरी को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों, अधिसूचनाओं और 30 जनवरी 2015 को किए गए संशोधनों का अध्ययन कर अगली सुनवाई में स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि संशोधित नियमों की जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल को क्यों नहीं दी गई और इसका प्रचार-प्रसार क्यों नहीं किया गया।

7 से 15 मार्च तक किरंदुल-विशाखापट्टनम पैसेंजर रद्द

दंतेवाड़ा। जिले के किरंदुल तक चलने वाली किरंदुल-विशाखापट्टनम पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस ट्रेन अब 9 दिनों तक किरंदुल नहीं जाएगी। इन दोनों ट्रेनों का अंतिम स्टॉपेज दंतेवाड़ा होगा, यहीं से विशाखापट्टनम के लिए रवाना होगी। किरंदुल और बचेली के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण के काम के चलते यह निर्णय लिया गया है। रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक के. संदीप द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 7 मार्च 2025 से 15 मार्च 2025 तक ट्रेन संख्या 58501 विशाखापट्टनम-किरंदुल पैसेंजर का दंतेवाड़ा अंतिम स्टॉपेज होगा। वहीं 8 मार्च 2025 से 16 मार्च 2025 तक ट्रेन संख्या 58502 किरंदुल-विशाखापट्टनम पैसेंजर किरंदुल की बजाय दंतेवाड़ा से रवाना होगी। इसी तरह विशाखापट्टनम से चलने वाली ट्रेन संख्या 18515 विशाखापट्टनम-किरंदुल नाइट एक्सप्रेस का 7 मार्च से 15 मार्च तक दंतेवाड़ा ही अंतिम स्टॉपेज होगा। वहीं 8 मार्च से 16 मार्च तक ट्रेन संख्या 18516 किरंदुल-विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस किरंदुल की बजाय दंतेवाड़ा से रवाना होगी।

पोस्टमार्टम करने के लिए कई घंटे देरी से पहुंचे डॉक्टर

कोरबा। कोरबा के मडिकल कॉलेज जिला अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई है। हृदयाघात से मौत के बाद ट्रक चालक को पोस्टमार्टम को लेकर परिजन डॉक्टरों को फोन लगा लगाकर थक गए, लेकिन चिकित्सक अस्पताल आने का नाम नहीं ले रहे थे। एसईसीएल की कुसमुंडा कोल परियोजना में नियोजित एक निजी कंपनी में ट्रक चालक के रुप में काम करने वाले नंद लाल चौहान की तबियत बीती रात अचानक खराब हुई। जिसे पहले बांकी स्थित एसईसीएल के विभागीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर उसे एक निजी चिकित्सक के पास ले जाया गए उसने भी उपचार करने में खुद को असमर्थ बताया। लिहाजा परिजन रात करीब दो बजे उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह 11 बजे पंचनामा की प्रक्रिया संपन्न हो गई लेकिन लेकिन डॉक्टर दो बजे तक पोस्टमार्टम के लिए नहीं पहुंचे। जिससे परिजनों को काफी परेशान होना पड़ा। जब उन्होंने ऊपर प्रबंधन से बात की तब जाकर डॉक्टर पीएम के लिए पहुंचे।

दो ट्रेलर में जोरदार टक्कर स्टेयरिंग में फंसा चालक

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में देर रात दो ट्रेलर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में वाहन चालक स्टेयरिंग में फंस गया। जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। उसके गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। घटना गौरेला वेंकटनगर मुख्यमार्ग की। जहां पर दौंजरा गांव के पास कोयले से भरे दो ट्रेलर की आमने-सामने की भिड़ंत हुई। गौरेला की ओर से आ रहे ट्रेलर के द्वारा विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में पूरा ट्रेलर के केबिन के हिस्से के परखच्चे उड़ गए और चालक स्टेयरिंग में फंस गया। घटना की जानकारी मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद स्टेयरिंग में फंसे चालक को ट्रेलर से बाहर निकाल कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर मौजूद चिकित्सकों के द्वारा चालक का प्राथमिक उपचार कर उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बिलासपुर सिम्स के लिए रेफर कर दिया गया है।

बाजार में घुसा अनियंत्रित ट्रक भीड़ ने चालक को लगाई मार

कोरबा। कोरबा के उरगा थाना अंतर्गत शक्ति मुख्य मार्ग भैसमा चौक के पास शराबी ट्रक चालक की करतूत सामने आई है। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बाजार में ट्रक को घुसा दिया। ट्रक की चपेट में आने से बाजार में एक नाबालिग स्कूटी सवार की मौत हो गई। इस हादसे के बाद बाजार में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। घटना मंगलवार की रात 9 बजे की बताई जा रही है। हादसे के बाद लोगों ने ट्रक चालक की पिटाई की और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे शराब भी ट्रक चालक को लेकर उरगा थाना पहुंचे। लोगों ने बताया कि मंगलवार की रात भैसमा बाजार चौक के समीप अचानक तेज रफ्तारअनियंत्रित ट्रक ने स्कूटी को चपेट में लेते हुए दीवार में जा टकराया। हादसे में एक नाबालिग ट्रक की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक परमेश्वर कंवर अपने परिजनों के साथ भैसमा बाजार सड़क किनारे एक कपड़ा दुकान में कपड़ा खरीदने आया हुआ था।

बस्तर का विश्व प्रसिद्ध फागुन मेला शुरू, 800 साल पुरानी परंपरा

दंतेवाड़ा। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध फागुन मेला की शुरुआत आज से हो गई है। 5 से 15 मार्च तक फागुन मेला लगेगा। हर दिन मां दंतेश्वरी की विशेष पूजा अर्चना होगी। खास बात यह है कि इस बार फागुन मेला में शामिल होने न सिर्फ छत्तीसगढ़ और बस्तर बल्कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों से भी देवी-देवता मेला में शामिल होने पहुंचे हैं।

मंदिर के पुजारी विजेंद्र नाथ जिया ने बताया कि मां दंतेश्वरी की पावन धरा में मड़ई का आयोजन हो रहा है। मड़ई का अर्थ हैं मंढाना या स्थापना करना। आज कलश की स्थापना होती है। 9 दिनों तक मां दंतेश्वरी के 9 रुपों की पालकी निकलती है। विधि विधान से आरती होती है।

पुजारी ने बताया कि सबसे खास बात यह है कि एक कलश में जल लेकर मां दंतेश्वरी की आरती की जाती है। यह विशेषता है। यह जल, नगर में स्थित मां शीतला के सरोवर से रोज शाम के समय लाया जाता है। माई जी की पालकी का नगर भ्रमण होने के

बाद इस जल से अभिषेक किया जाता है।

पुजारी के मुताबिक फागुन मड़ई मेला में देवी देवताओं की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। बस्तर संभाग के साथ ही ओडिशा के बार्डर, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र से भी देवी देवताओं के प्रतीक जैसे छत्र, छड़ी, पताका के साथ उनके पुजारी और सेवादार दंतेवाड़ा में पूरे 9 दिन तक उपस्थित रहते हैं।

पुजारी का कहना है कि यहां कई परंपराओं का नाट्य चित्रण होता है। यह सभी रस्में देखने लायक होती हैं। यहां आखेट यानी शिकार का अभिनय किया जाता है। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं। यहां 9 दिनों तक बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं।

मंदिर के पुजारी ने बताया कि बुधवार शाम 4 बजे मां दंतेश्वरी मंदिर से मदन केसरी की पहली पालकी निकाली जाएगी, जिसमें गांव-गांव से आए देवी देवता शामिल होंगे। यह पालकी नारायण मंदिर तक ले जाई जाएगी और नारायण मंदिर में माता की पूजा के बाद वापस दंतेश्वरी मंदिर लाई जाएगी। यह प्रक्रिया हर रोज पूरी की जाएगी। आखेट का कार्यक्रम मध्य रात्रि को किया जाएगा। आखेट की कई रस्म अदा कर 800 साल पुरानी परंपरा निभाई जाएगी।

दरअसल पुरानी मान्यताओं के अनुसार करीब 800 साल पहले आखेट (शिकार) प्रचलित था। जंगली जानवर किसानों की फसलें खराब कर देते थे। ग्रामीण इस समस्या के निदान के लिए राजा महाराजा के पास गए। तब उस समय के राजा ने जानवरों का शिकार करना शुरू किया। राजा जब शिकार करते तो किसी दैवीय शक्ति की वजह से तीर लगने के बाद भी जानवर मरते नहीं थे।

इसके बाद राजा ने जानवरों के शिकार के लिए आराध्य देवी माता दंतेश्वरी की आराधना कर अनुमति ली। फिर शिकार शुरू किया गया। यह अनुमति लेने वाले दिन से ही फागुन मड़ई की शुरुआत हुई। इसके बाद धीरे धीरे स्थानीय देवी देवताओं को भी इस मड़ई में शामिल किया जाने लगा।

दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी विजेंद्र नाथ जिया ने बताया कि फागुन मेला आखेट (शिकार) के लिए प्रसिद्ध है। इसमें रस्में तिथि और समय के अनुसार 10 से 11 दिनों तक चलती हैं। अब शिकार का नाट्य रूपांतरण कर परंपरा निभाई जाती है।

पंचायत सचिव निलंबित, महिला पंचों की जगह पतियों को दिलाई थी शपथ

कवर्धा। जनपद पंचायत पंडरिया के ग्राम पंचायत परसवारा में नवनिर्वाचित पंच प्रतिनिधियों के प्रथम सम्मेलन में महिला पंचों की अनुपस्थिति में उनके पतियों को नियम विरुद्ध पंच पद का शपथ दिलाने का मामला सामने आया है। इसकी खबर लल्लूराम डॉट काम ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। इस मामले में संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत सीईओ अजय कुमार त्रिपाठी ने ग्राम पंचायत परसवारा के सचिव प्रणीवर सिंह ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत परसवारा में 3 मार्च को नवनिर्वाचित पंचों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें सचिव ने अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंडरिया ने प्रथम दृष्टियां सचिव को दोषी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 में निहित प्रावधानों के अनुसार सचिव प्रणवीर सिंह ठाकुर को निलंबित करते हुए जनपद पंचायत पंडरिया में संलग्न किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, साय ने मंत्रियों के साथ की दौरे को लेकर बैठक

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। वे बिलासपुर में आयोजित लोकार्पण एवं भूमिपूजन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम के दौरे की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बैठक ली। बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, मंत्री ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, केदार कश्यप के अलावा धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, धर्मजीत सिंह, बिलासपुर रेंज के आईजी संजीव शुक्ला और एसपी रजनीश सिंह मौजूद थे।

राजधानी में शुरू हुआ अवैध ठेला-गुमटी हटाने का अभियान

रायपुर। शहर सरकार के बदलते ही राजधानी की ट्रैफिक को सुधारने के लिए कवायद शुरू हो गई है। इस कड़ी में बुधवार को अवैध दुकानों और ठेला को हटाने का अभियान शुरू हुआ। नगर निगम के अमले ने पुलिस बल की मौजूदगी में जय स्तंभ चौक से लेकर फाफाडीह चौक तक सड़क के इर्द-गिर्द बने अवैध दुकानों, ठेलों और गुमटियों को बुलडोजर से हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान पुलिस और नगरीय निकाय की टीम से दुकानदारों की झूमाझटकी भी हुई।

राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रमोट हुए आईएएस अफसरों को बैच हुआ अलॉट

रायपुर। राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नत हुए अधिकारियों को उनके बैच का आवंटन कर दिया गया है। केंद्र सरकार के आदेशानुसार 2021 से 2023 की चयन सूची में शामिल अधिकारियों की वरिष्ठता और बैच निर्धारण किया गया है। इस संबंध में जारी किये गए आदेश के अनुसार कुल 10 अधिकारी हीना अनिमेष नेताम, अश्विनी देवांगन, डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, आशुतोष पांडे, अजय कुमार अग्रवाल, रीता यादव, लोकेश कुमार, प्रकाश कुमार, गजेन्द्र सिंह ठाकुर और तनुजा सलाम का नाम शामिल है। 2021 चयन सूची में हीना अनिमेष नेताम को 2016 बैच और अश्विनी देवांगन को 2018 बैच मिला। 2022 चयन सूची में डॉ. रेणुका श्रीवास्तव और आशुतोष पांडे को 2019 बैच में स्थान दिया गया। 2023 चयन सूची में अजय कुमार अग्रवाल, रीता यादव, लोकेश कुमार, प्रकाश कुमार, गजेन्द्र सिंह ठाकुर और तनुजा सलाम को 2019 बैच में शामिल किया गया। इस बैच आवंटन के लिए आईएएस (वरिष्ठता विनियमन) नियम, 1987 के तहत वेटेज फॉर्मूला लागू किया गया है, जिससे अधिकारियों को उनके तत्काल वरिष्ठों के अनुसार उचित स्थान दिया गया है।

रायपुर निगम कमिश्नर होंगे विश्वदीप अविनाश मिश्रा बने धमतरी कलेक्टर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव संपन्न होने के बाद आचार संहिता समाप्त होते ही प्रशासनिक तबादले शुरु हो गए है। इसी कड़ी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया है। रायपुर कमिश्नर अविनाश मिश्रा को धमतरी का कलेक्टर बना दिया गया है वहीं विश्वदीप को उनकी जगह पर रायपुर कमिश्नर बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव अन्वेष घृतलहरे के हस्ताक्षर से जारी आदेश मुताबिक राज्य शासन एतद द्वारा श्री अभिजीत सिंह, भा.प्र.से. (2012). विशेष सचिव, गृह एवं जेल विभाग तथा अति प्रभार विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सचिव लोक सेवा आयोग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-दुर्ग के पद पर पदस्थ करता है। अबिनाश मिश्रा, भा.प्र.से. (2018), आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, स्मार्ट सिटी, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-धमतरी के पद पर पदस्थ करता है। सुश्री रेना जमील, भा.प्र.से. (2019), उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को उनके बर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, लोक सेवा आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है। विश्वदीप, भा.प्र.से. (2019). मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, स्मार्ट सिटी, रायपुर का अति. प्रभार सौंपता है। 5/ श्री कुमार बिश्वरंजन, भा.प्र.से. (2020), चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चिप्स को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है।

दुर्ग-निजामुद्दीन-दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस में एसी-3 कोच की सुविधा

रायपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा व अधिकाधिक यात्रियों को कंफ़र्म बर्थ उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली गाड़ी संख्या 22867/22868 दुर्ग-निजामुद्दीन-दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस में एक एसी-3 कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा गाड़ी संख्या 22867 दुर्ग-निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस में 7 मार्च से 14 मार्च तक तथा गाड़ी संख्या 22868 निजामुद्दीन-दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस में 8 मार्च से 15 मार्च तक उपलब्ध रहेगी। इस सुविधा की उपलब्धता से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले अधिकाधिक यात्री लाभान्वित होंगे।

शासकीय भूमि के आवंटन का मामला सदन में गूंजा

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने पूछा- 56 करोड़ की जमीन 9 करोड़ में कैसे दे दी? मंत्री बोले, निरस्त हो चुका है आवंटन

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के सातवें दिन की कार्यवाही जारी है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान अमलीडीह की शासकीय भूमि के आबंटन का मामला गरमा गया। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से सवाल किया कि इस भूमि का आबंटन निरस्त करने का कारण क्या था। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि नियमों में बदलाव के कारण यह आबंटन रद्द कर दिया गया था।

प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने पूछा कि जमीन आबंटन निरस्त होने का कारण क्या है?

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में नियम में बदलाव की वजह से आबंटन निरस्त कर दिया गया था।

धरमलाल कौशिक ने पूछा कि जब भूमि का आबंटन निरस्त किया गया तब बाजार की दर क्या थी? चराई की भूमि का आबंटन नहीं किया जा सकता है। 56 करोड़ रुपए पटाया जाना था लेकिन सिर्फ 9 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई थी। अधिकारियों ने जो इस तरह से काम किया था उनके खिलाफ क्या

कार्रवाई की जाएगी?

इस पर जवाब देते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि भूमि का आबंटन की प्रक्रिया चल रही थी। राशि नहीं पटाई गई थी। शासन ने आबंटन निरस्त कर दिया था। विधायक धरमलाल कौशिक ने पूछा कि भूमि रिकॉर्ड में किसके नाम पर है?

राजस्व मंत्री ने बताया कि आबंटन कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, जब राशि पटाई जाती है। राशि जमा करने के पूर्व ही आबंटन रद्द कर दिया गया था। रिकॉर्ड में भूमि शासन के नाम पर ही दर्ज है। कलेक्टर द्वारा डिमांड लेटर दिया ही नहीं गया था।

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने पूछा कि आबंटन की प्रक्रिया गलत थी। इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? सरकार की जमीन की अफरा तफरी करेंगे? 56 करोड़ की जमीन को 9 करोड़ रुपए में कर देंगे?

इस पर जवाब देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि आबंटन किया ही नहीं गया।

भाजपा विधायक कौशिक ने पूछा कि सरकारी जमीन में बंदरबांट की गई है। यह सिर्फ एक प्रकरण नहीं है। मंत्री सदन में असत्य कथन कर रहे हैं।

जिसपर भाजपा विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि मेरी ही शिकायत पर रामा बिल्डकॉन को आबंटित जमीन निरस्त की गई थी, लेकिन सदन में दिये गए जवाब में रिकॉर्ड में जमीन बिल्डकॉन के नाम पर ही दर्ज दिख रहा है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि निरस्त कर दिया गया है।

सिकलसेल संस्थान में नहीं सिकलसेल मरीजों के इलाज की सुविधा!

रायपुर। सिकलसेल संस्थान में सिकलसेल के मरीजों की इलाज की सुविधा नहीं होने का मामला सदन में उठा। ध्यानाकर्षण के ज़रिए भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मामला उठाया। अजय चंद्राकर ने कहा कि- पीड़ित मरीज अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रदेश में सिकलसेल बीमारी से 25 लाख लोग पीड़ित है। सिर्फ एक ही चिकित्सा संस्थान रायपुर में है लेकिन पर्याप्त विशेषज्ञ नहीं है। कोई रिसर्च नहीं किया जाता। संचालन के लिए स्वयं का भवन तक नहीं है। मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। स्वाथ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि- राज्य में एकमात्र सिकलसेल संस्थान है। राज्य के सरकारी चिकित्सालय में सिकलसेल प्रबंधन सेल शुरू किया गया है। सिकलसेल को लेकर वैज्ञानिकों ने 19 शोध पत्र प्रकाशित किया है। चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सिकलसेल सेंटर ऑफ़ एक्सिलेंस में बोनमैरो ट्रांसप्लांट की व्यवस्था शुरू की जा रही है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- जब मैं स्वास्थ्यमंत्री था तक सिकलसेल संस्थान शुरू किया गया था। भूपेश सरकार तो सिर्फ भवन के लिए नारियल फोड़कर चुप बैठ गई। मंत्री बताए कि संस्थान में कितने डॉक्टर और विशेषज्ञ हैं? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- प्रदेश में सिकलसेल के लिए बड़ा काम किया गया है। 23 जून 2023 को भूपेश सरकार ने आनन फ़ानन में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के लिए भूमिपूजन कर लिया था। हमारी सरकार आने के बाद से अब तक 11 बैठके हम कर चुके हैं। 180 का सेटअप है। 28 कार्यरत हैं। इनमें से 4 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। हमारा प्रयास होगा कि जल्द से जल्द डॉक्टरों की भर्ती की जाए। जब तक भर्ती नहीं होती तब तक डॉक्टरों को अटैच कर कार्यवाही की जाएगी। अजय चंद्राकर ने पूछा- संस्थान में कितनी मशीन उपलब्ध है, और कितने मानव संसाधन है? स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि-आवश्यकतानुसार चार उन्नत मशीनें उपलब्ध हैं। जांच के लिए मानव संसाधन उपलब्ध है। प्रतिदिन 60 मरीजों की जांच की जा रही है। नौ तकनीशियन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए हैं। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बनाने के लिए कितने दिनों में बोनमैरो ट्रांसप्लांट, शोध आदि की अनुमति मिल जाएगी? संस्थान के ठीक बाजू का बंगले में मंत्री रहते थे। उस बंगले की जमीन को भी संस्थान के लिए दिया जाना था। क्या किसी तरह की आर्थिक अनियमितता की शिकायत पाई गई है? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- करीब दो एकड़ जमीन थी। किसी भी तरह की आर्थिक अनियमिता की जानकारी नहीं है। यह दुर्भाग्य है कि किसी भी स्वास्थ्य मंत्री ने सिकलसेल संस्थान को मजबूत करने के लिए काम नहीं किया है। यह मेरी प्राथमिकता में है। अजय चंद्राकर जिस आर्थिक अनियमितता की जानकारी दे रहे हैं, उसका परीक्षण किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर जांच कराई जाएगी।

सरकार ने चार सालों में हेलीकॉप्टर किराए पर 249 करोड़ रुपए से अधिक किया खर्च

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते चार सालों में किराए पर लिए गए हेलीकॉप्टर के लिए 249 करोड़ 15 करोड़ 42 हजार 818 रुपए का भुगतान किया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस विधायक इंद्र साव के सवाल के जबाव में दी।

कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल किया कि छत्तीसगढ़ शासन के विमानन विभाग ने वर्ष 2021-22 से 2024-25 (31 जनवरी 2025) तक किन-किन निजी कंपनियों से हेलीकाप्टर किराये पर लिया। इन कंपनियों को किस दर पर राशि का भुगतान किया गया है। इसके अलावा क्या विमानन विभाग ने शासकीय विमान की खरीदी की थी।

यही नहीं वर्तमान में यह विमान उपयोग में है अथवा नहीं?

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि राज्य शासन ने वर्ष 2006-07 में डबल ईंजन युक्त शासकीय विमान किंग एयर बी-200, वीटी-सीटीजी की खरीदी की थी, यह विमान दिसंबर 2006 से उपलब्ध है। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर टेण्डर के जरिए निजी कंपनियों से हेलीकॉप्टर किराए पर लिया जाता है।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि वर्ष 2021-22 में ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा से 11 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 6 करोड़ 66 लाख 42 हजार 783 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं एयर किंग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड से 21 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 18 करोड़ 15 लाख 92 हजार 159 रुपए का भुगतान किया गया।

इसी तरह वर्ष 2022-23 में ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा से 41 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 59 करोड़ 99 लाख 44 हजार 105 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं एयर किंग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड से 16 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 18 करोड़ 71 लाख 29 हजार 947 रुपए का भुगतान किया गया।

वर्ष 2023-24 में ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा से 51 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 89 करोड़ 50 लाख 33 हजार 999 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं वर्ष 2024-25 में ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा से 37 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 56 करोड़ 11 लाख 99 हजार 825 रुपए का भुगतान किया गया।

सर्पदंश से मौत पर खेला गया मुआवजे का खेल

रायपुर। सर्पदंश से होने वाली मौतों पर मुआवजे के नाम पर अधिकारियों ने करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया। सदन में भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला द्वारा लगाए गए आरोप पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जांच की घोषणा की।

विधायक सुशांत शुक्ला ने विभाग की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर कहा कि सर्पलोक कहे जाने वाले जशपुर में 96 लोगों की सर्पदंश से मौत हुई, जबकि बिलासपुर में 431 लोगों की मौत हो जाती है, जो संभव नहीं। मुआवजे में करोड़ों की गड़बड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने आसंदी से कहा कि सांप फर्जी था कि आदमी फर्जी था।

मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पहली बार ये जानकारी में आया है। ऐसा है तो विधायक जानकारी दें, इसकी जांच कराई जाएगी। सुशांत शुक्ला ने कहा कि पहले जांच हुई है क्या? जबकि पहले भी शिकायत हुई है। राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों का घोटाला हुआ है। इसकी सचिव स्तर के अधिकारी से जांच करायेंगे क्या?

मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुझे शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच और कार्रवाई दोनों होगी। इसके साथ मंत्री टंकराम वर्मा की सदन में घोषणा कि बिलासपुर में सर्पदंश से 431 मौत की जांच कराई जाएगी।

रायपुर में सात तारीख को होगा सभापति का चयन: मीनल चौबे

रायपुर। सभापति का चयन को लेकर मेयर मीनल चौबे ने कहा कि आगामी सात तारीख को सभापति का चयन होगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में संगठन का निर्णय महत्वपूर्ण होता है। संगठन जो भी आदेश करती है, उसके अनुसार हम काम करते हैं।

कर वसूली के लिए चार सौ करोड़ का टारगेट पर मेयर मीनल चौबे ने कहा कि नगर निगम का जो मुख्य आय का स्रोत है, वह हमारा राजस्व है। उन्होंने कहा कि सख्त निर्देश है कि हम मध्यम वर्गीय लोगों पर हम सख्ती दिखाते हैं, लेकिन जो बड़े और रसूखदार हैं। जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनसे भी बराबर रिवेन्यू वसूली की जाए, तभी जो नगर निगम का काम है वह ठीक ढंग से चल पाएगा।

नगर निगम की ओर से सूची तैयार की गई है, उसमें नेताओं का भी नाम शामिल है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस-बीजेपी का विषय नहीं है। बकायादार बकायादार होता है। उसके दलों से कोई संबंध नहीं है। जो भी बकायदार होगा, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अधीन उन पर कार्रवाई की जाएगी। कर उनको देना ही पड़ेगा।

डॉग बाईट के विषय में उन्होंने कहा कि जब से मैं मेयर बनी हूं, इस विषय में काम कर रही हूँ। इसके लिए नगर निगम के डॉक्टर के टीम के माध्यम से बात कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ एनजीओ से भी बात कर रहे हैं। उनसे सुझाव लिया जाएगा, कि किस प्रकार इन घटनाओं से शहरवासियों और जनता को छुटकारा मिलेगा।

रायपुरा में मेयर को लड्डू से तौलकर कार्यकर्ताओं ने किया सम्मान

राजधानी रायपुर के नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे ने पदभार ग्रहण कर ली हैं। आज बुधवार को रायपुरा में मेयर मीनल चौबे को 70 किलो लड्डू से तौलकर कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया। माधव राव सप्रे वार्ड के कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यक्रम आयोजित की गई थी।

इस मौके पर मेयर मीनल चौबे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद रायपुर के माधव राव सप्रे वार्ड में कार्यकर्ताओं की ओर से लड्डू से तौलकर मेरा सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में मुझे सबसे ज्यादा लीड रायपुरा से हुई है। समस्त रायपुरावासियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि रायपुरा की अब चहुँमुखी विकास होगा। कार्यक्रम के आयोजक संजय सिंह मंडल महामंत्री ने कहा कि पिछले दस दिनों से कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कर रहे थे। मेयर पदभार ग्रहण करने के बाद कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान 70 किलो लड्डू से मेयर मीनल चौबे को तौलकर उनका सम्मान किया गया।

मनरेगा के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के नाम पर सौंपा ज्ञापन

छंटनी रोकने और लंबित वेतन दिलाने की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ विकास आयुक्त कार्यालय ने हाल ही में मनरेगा विभाग में छटनी के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर मनरेगा के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा के नाम पर ज्ञापन सौपा है। कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से विभाग में छटनी को रोकने और लंबित वेतन दिलवाने की मांग की है।

बता दें, हाल ही में छत्तीसगढ़ विकास आयुक्त कार्यालय ने पत्र जारी कर महात्मा गांधी मनरेगा के कुल स्वीकृत पदों में से खाली पद से अतिरिक्त संख्या में अगर कर्मचारियों की नियुक्ति कलेक्टर दर पर की गई हो, तो ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल समाप्त की जाए। किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत पद की तुलना में अधिक कर्मचारियों को नियोजित न की जाए।

प्रदेश महामंत्री प्रवीण कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 800 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना विभाग में विगत 10 वर्षों से कार्यरत हैं। सभी श्रमिक दर पर कार्यरत हैं। लेकिन इस आदेश से हम सभी कर्मचारी इस आदेश से

हतप्रभ हैं।

प्रवीण सिंह ने कहा कि मनरेगा विभाग के साथ-साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों एवं लोकसभा, विधानसभा, त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन दिन-रात किया जा रहा है। इनके बावजूद हमारी सेवाएं समाप्त की जा रही है, जों अनुचित है। प्रवीण ने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों सें मनरेगा विभाग में संविदा पदों पर भर्ती नहीं हुई, जिनके कारण मनरेंगा कार्यों कों समय सीमा में पूरा करनें के लिए हम सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जनपद व जिला में नियुक्त किया गया है।

आवास, महतारी वंदन व शासन के अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को समय पर पूरा करनें के लिए भी हमारी ड्युटी लगाया जाता है। परंतु इस प्रकार आदेश जारी कर हमें एकाएक कार्य से निकाला जा रहा है। जिसके कारण हम बेरोजगार हो जायेंगें। हमारे परिवार के भरण पोषण में विकट समस्या आ जाएगी।

वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीमांत प्रजापति ने बताया कि मनरेगा कर्मचारियों ने अतिरिक्त कार्यरत कलेक्टर दर कर्मचारियों के लिए जारी आदेश कों स्थगित कर उन्हें समायोजित कर यथावत कार्य में रखनें के लिए आदेश जारी करने की मांग की है।

पीसीसी चीफ बैज ने फिर लगाया जासूसी का आरोप

रायपुर। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने फिर जासूसी का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, जासूसी और निगरानी खत्म नहीं हुई है बल्कि और बढ़ गई है। सरकारी बंगले आने वाली सभी गाड़ियों की निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखे पत्र का अब तक जवाब नहीं आया है। इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए।

बैज ने कहा, जिला पंचायत और जनपद के जीते प्रत्याशियों पर निगरानी रखकर उन्हें धमकाया जा रहा। मेरा मोबाइल भी सर्विलिएंस पर रखा गया है। बीजेपी के नेता भी हमसे बात करने घबरा रहे हैं। वहीं सेक्स सीडी मामले में भूपेश बघेल को क्लीन चिट मिलने

पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, न्याय की जीत हुई है। उन्होंने सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

पीसीसी चीफ ने कहा, आलाकमान ने चुनाव को लेकर रिपोर्ट मांगी है। पंचायत चुनाव और ईडी की कार्रवाई की रिपोर्ट लेकर दिल्ली जाएंगे। पंचायत चुनाव में सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने कहा, ईडी के अफसरों को कांग्रेस भवन भेजा। नौ घंटे पूछताछ की। बलौदाबाजार के जीते प्रत्याशियों को बलौदाबाजार आगजनी मामले में फंसाने धमकाया जा रहा। अधिकारी चिट्ठा निकालकर खुद अध्यक्ष बना रहे। सभी की रिपोर्ट लेकर दिल्ली जाऊंगा।

अवैध ठेले गुमटियों पर कार्रवाई करने को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़े कब्जों पर कार्रवाई न करने पर सवाल उठाते हुए कहा, ये सरकार गरीबों पर अत्याचार कर रही है। गरीबों के पेट में लात मारने का काम कर रही।

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH, WATER RESOURCES DEPARTMENT
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER
MAHANADI PROJECT, RAIPUR (CHHATTISGARH)

e-PROCUREMENT TENDER NOTICE
eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

(First Call)

System Tender No. 164539/ NIT No.: 11/SAC/24-25 Dated: 03.03.2025
Online Tenders are invited for the following work up to 24.03.2025 at 17.30 Hours.
Name of work- Construction of Water Resources Office Building at Balodabazar under Mahanadi Project.
Probable Amount of Contract:- **Rs. 236.91 Lakhs**
(As per S.O.R dated 01.08.2010 and amended upto dated 22.08.2022).
The details can be viewed and downloaded online directly from the Government of Chhattisgarh Integrated e-Procurement Portal **(https://eproc.cgstate.gov.in) from Date 10.03.2025, at 17.31 Hours. (IST) onwards.**
NOTE:- All eligible/intrested contractors/bidders are mandated to get enrolled on the Integrated e-procurement portal **(https://eproc.cgstate.gov.in)** and get approval on specific vendor class from PWD under Centralized Contractor/Supplier Registration in order to down-load the tender documents and participate in the subsequent bidding process.

Executive Engineer
Water Management Division No. 2, Balodabazar
For, Chief Engineer, Mahanadi Project
Raipur (C.G.)

G-242505706/6

वाजिब है राष्ट्रपति जेलेंस्की का क्रोधित होना?

विकास मिश्रा

दुनिया तो यह मान कर ही चल रही थी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के सामने ट्रम्प की शर्त मान लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ट्रम्प को अपनी चाल पर भी बहुत भरोसा था। जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे भी लेकिन उन्होंने जो तेवर दिखाए, वो कोई आसान काम नहीं था। अमेरिका का हर राष्ट्रपति खुद को तुर्रम खां समझता है और ट्रम्प तो और भी तीखे तेवर में हैं। अपनी दूसरी पारी में वे अब तक जिन राष्ट्राध्यक्षों से भी मिले हैं, भयानक तेवर दिखाए हैं लेकिन किसी ने भी जेलेंस्की जैसी हिम्मत नहीं दिखाई! जेलेंस्की बेशक कमजोर स्थिति में हैं लेकिन उन्होंने फिलहाल अपने तेवर दिखाकर खुद के इस वादे को मजबूत किया है कि वे देश नहीं बेचेंगे। यह कितनी विचित्र बात है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इस वक्त रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है लेकिन जंग खत्म कराने के लिए ट्रम्प की पहल पर जो पहली बैठक हुई, उसमें यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि तक नहीं था! जेलेंस्की का क्रोधित होना वाजिब था इसलिए उन्होंने कहा भी कि यूक्रेन की सहमति और सहभागिता के बगैर जंग कैसे रुक सकती है और शांति कैसे आ सकती है? लेकिन ट्रम्प तो यह मान कर चल रहे हैं कि अमेरिका की मदद के बगैर रूस से लड़ने की ताकत यूक्रेन में नहीं है। बात काफी हद तक सही भी है। अमेरिका और यूरोप ने यदि यूक्रेन का साथ नहीं दिया होता तो रूस उसे कब का हजम कर गया होता। मदद के लिए अमेरिका इसलिए सामने आया क्योंकि अमेरिकी नीति साम्राज्यवाद के खिलाफ रही है। वह खुद को लोकतंत्र का स्वयंभू रक्षक मानता रहा है। इसलिए जहां भी उसके हिसाब से लोकतंत्र खतरे में होता है, वहां वह बिना बुलाए पहुंच जाता है। लेकिन ट्रम्प की सोच बिल्कुल अलग है। वे यह मानकर चलते हैं कि यूक्रेन की मदद करना अमेरिका की गलती थी। उनके हिसाब से अभी तक इस जंग में अमेरिका 500 बिलियन डॉलर की सहायता यूक्रेन को दे चुका है। वे यह भी मानते हैं कि यह जंग जेलेंस्की की 'सनक' के कारण हुई। यानी वे यह मान कर चल रहे हैं कि इसमें रूस की कोई गलती नहीं है! है न विचित्र बात! लेकिन ट्रम्प को यह सब विचित्र नहीं लगता क्योंकि वे तो फिलहाल इस जुगाड़ में हैं कि अमेरिका के 500 बिलियन डॉलर कैसे वापस आ जाएं। ट्रम्प ने खुल्लमखुल्ला कहा कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है, वहां मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट निकालने का अधिकार अमेरिका को मिलना चाहिए। यह बात जेलेंस्की को जंची नहीं और उन्होंने साफ कह दिया कि वे देश बेचने वालों में से नहीं हैं। कमाल देखिए कि ट्रम्प के इस प्रस्ताव पर रूस ने हामी भी भर दी कि यदि अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल उसके कब्जे वाली जमीन से निकालता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है! चूंकि यूक्रेन जंग से बुरी तरह बर्बाद हुआ है इसलिए जेलेंस्की भी चाह रहे थे कि कोई सम्मानजनक समझौता हो जाए और जंग समाप्त हो। उन्होंने कहा भी कि यदि सम्मान के साथ कोई समझौता होता है तो पद भी छोड़ने को तैयार हैं। जंग खत्म हो लेकिन यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए लेकिन इस मसले पर ट्रम्प बात करने को ही तैयार नहीं हैं। जेलेंस्की पर जबर्दस्त दबाव था इसलिए यह माना जाने लगा और विश्व मीडिया में यह प्रचारित भी किया गया कि जेलेंस्की अमेरिका आ रहे हैं और रेयर अर्थ मिनरल के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में सामान्य रूप से यह समझिए कि यह खनिज आधुनिक तकनीक के सभी साधनों में काम आता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार हो या फिर आधुनिक हथियार। रेयर अर्थ मिनरल्स की करीब 70 प्रतिशत वैश्विक आपूर्ति अभी चीन करता है। ट्रम्प की चाहत है कि यूक्रेन का भंडार यदि उन्हें मिल जाए तो चीन के दबदबे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

तमिलनाडु में भी उठी हिंदी समर्थक आवाज

उमेश चतुर्वेदी

संस्कृति का उपादान और उसके नैरंतर्य का जरिया होने की वजह से भाषाएं उन लोगों के लिए भावनात्मक मुद्दा होती हैं, जो उन्हें प्राथमिक जुबान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए तमिलनाडु की इसी भावना का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब हिंदी के समर्थन में तमिलनाडु के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। श्रीधर वेंबु तमिल माटी के ही सपूत हैं, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और कारोबार की दुनिया में उनकी कंपनी जोहो का डंका बज रहा है। यही श्रीधर वेंबु खुलेतौर पर कहने लगे हैं कि आइए हम हिंदी सीखें। हिंदी ना जानने की वजह से हो रही कारोबारी दुश्वारियों को वे समझ रहे हैं, इसीलिए वे ना सिर्फ हिंदी सीख रहे हैं, बल्कि इसकी मुनादी भी कर रहे हैं।

श्रीधर ने ट्वीटर पर जब हिंदी सीखने की अपील की तो इसे स्टालिन की भाषायी राजनीति के जवाब के तौर पर देखा जाने लगा। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। क्योंकि तमिल संस्कृति और भाषा के सम्मान के नाम पर वह तमिल भावनाओं को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में वे कभी हिंदी को साम्राज्यवादी बताते हैं और जब हिंदी पर यह आरोप साबित नहीं हो पाता तो वह हिंदी पर यह आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हटते कि अपने हृदय प्रदेश की बोली-बानियों और छोटी भाषाओं के अस्तित्व को उसने निगल लिया है। स्टालिन का यह कहना कि हिंदी ने भोजपुरी, अवधी, अंगिका आदि भाषाओं के अस्तित्व को नष्ट कर दिया है, उसी आरोपबाजी का विस्तार है। जबकि हकीकत यह है कि हिंदी ने अपने हृदय प्रदेश की किसी भी भाषा के अस्तित्व को कोई चोट नहीं पहुंचाई है। उलटे हिंदी इन भाषाओं के बीच संपर्क भाषा के रूप में काम कर रही है। वह उन भाषाओं से शब्दों को लेकर समृद्ध भी हो रही है। अवधी, भोजपुरी, बैसवाड़ी या ब्रजभाषी जब अपने भाषा समुदाय से दूर के लोगों से मिलतें हैं, उनके सहज संवाद की भाषा हिंदी होती है। इस

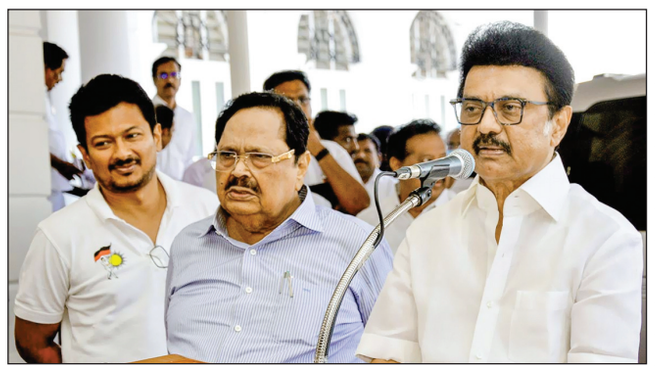

संवाद प्रक्रिया में वह हर भाषा से कुछ शब्द लेती है, उन्हें दोनों के बीच के कड़ी के रूप में स्थापित करती है और इस तरह खुद भी समृद्ध होती है और अपनी बोली या उपभाषाओं को भी ताकतवर बनाती है।

महात्मा गांधी ने तमिल और तेलुगू युवाओं से एक सौ सात साल पहले हिंदी सीखने की अपील की थी। उनके ही आह्वान पर 17 जन 1918 को एनी बेसेंट और रामास्वामी अय्यर ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी। गांधी जी का सपना था कि तमिल और तेलुगू जैसे अहिंदीभाषी इलाकों के हिंदी को ना सिर्फ सीखें, बल्कि हिंदी को लेकर अपने राज्यों में माहौल बनाएं। गांधी जी का वह सपना सौ साल से अधिक वक्त के बाद सच होता नजर आ रहा है। श्रीधर वेंबू जैसे घोर तमिलभाषी व्यक्ति का हिंदी के समर्थन में सामने आना और उनके साथ तमिलनाडु ही नहीं, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना आदि के लोगों का खड़ा होना मामूली बात नहीं है। हिंदी को लेकर तमिलनाडु के आम जन की जो छवि कम से कम उत्तर भारत में बनी है, तमिलनाडु से हिंदी के समर्थन में उठने वाली ये आवाजें उसे खंडित कर रही हैं। श्रीधर वेंबु जैसी महत्वपूर्ण स्वरों का हिंदी के समर्थन में उठना तमिलनाडु के आमजनों की कथित हिंदी विरोधी छवि का भी जवाब है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे आर्थिक विचारक एस गुरूमूर्ति तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक हलके की महत्वपूर्ण आवाज हैं। लेकिन हिंदी को लेकर तमिलनाडु में जो सामान्य धारणा रही है, उसकी वजह से हिंदी समर्थक उनके सुर को तमिल माटी में तवज्जो देने से बचा जाता रहा है। लेकिन श्रीधर वेंबु की आवाज और उनके समर्थन में सोशल मीडिया मंचों पर उमड़े युवा स्वरों ने गुरूमूर्ति की हिंदी समर्थक आवाज को ताकत दी है। गुरूमूर्ति भी खुलकर हिंदी विरोधी राजनीति के खिलाफ अपने तर्क दे रहे हैं और उन तर्कों को तमिलनाडु में ध्यान से सुना-पढ़ा जा रहा है। हिंदी का समर्थन करते हुए श्रीधर यह भी कह रहे हैं कि उनकी कंपनी का कामकाज तमिलनाडु की तुलना में दूसरे राज्यों में ज्यादा है। जहां उनकी कंपनी अपने तमिल अधिकारियों और प्रोफेशनल को भेजने में हिचकती है, क्योंकि वे दूसरे राज्यों में सहज संवाद विशेषकर जमीनी स्तर पर नहीं कर पाते।

1965 में तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ था। उसकी वजह यह थी कि संवैधानिक प्रावधानों के चलते हिंदी को राजकाज की भाषा का स्थान लेने के लिए पंद्रह साल की अवधि 25 जनवरी 1965 को पूरी हो रही थी। तब क्षेत्रीय द्रविड़ राजनीति को हिंदी विरोध में अपनी राजनीतिक राह दिखी। तमिल उपराष्ट्रीयता को उन्होंने हिंदी विरोध के नाम उभारा और स्थानीय लोक को अपने पक्ष में लामबंद किया। इसकी वजह से भारत सरकार को हिंदी को राजकाज की भाषा बनाने के संवैधानिक आग्रह को अनंत काल के लिए कानूनी तौर पर टालना पड़ा। इन अर्थों में तमिलनाडु का हिंदी विरोधी आंदोलन सफल कहा जाएगा। उसी वक्त से तमिलनाडु के सरकारी विद्यालयों में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू नहीं है, जबकि तकरीबन समूचे देश में पढ़ाई के लिए त्रिभाषा यानी स्थानीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई की सुविधा लागू है। साल 2020 में आई नई शिक्षा नीति में फिर से प्राथमिक स्तर से ही त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने की बात की गई है और स्टालिन का हिंदी विरोध इसी फॉर्मूले के विरोध के साथ उभरा है।

तमिलनाडु के सरकारी विद्यालयों से हिंदी भले ही दूर हो, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम लागू करने वाले विद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। अखिल भारतीय नौकरियों के मद्देनजर स्थानीय लोग अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड वाले स्कूलों में पढ़ा तो रहे ही हैं, बच्चों को अलग से हिंदी की कोचिंग भी दिला रहे हैं। गुरूमूर्ति के अनुसार, तमिलनाडु में सीबीएसई बोर्ड वाले स्कूलों में साठ लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जबकि तमिलनाडु सरकार के विद्यालयों में करीब 83 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि तमिलनाडु सरकार के विद्यालयों के बच्चे हिंदी से दूर हैं, जिनकी संख्या सीबीएसई विद्यालयों के विद्यार्थियों का करीब एक सौ बीस गुना ज्यादा है। तमिलनाडु की आज की प्रौढ़ हो चुकी पीढ़ी में एक वर्ग ऐसा भी है, जो सोचता है कि हिंदी विरोधी आंदोलन में हिस्सा लेकर उसने गलती की। इस गलती को सुधारने के लिए वह पीढ़ी अपने बच्चों को हिंदी से घृणा करना सीखने-सिखाने से बचती है। इसके अलावा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा अब तक सवा दो करोड़ से ज्यादा लोगों को हिंदी सिखा और पढ़ा चुकी है।

इसी साल उससे जुड़े विद्यार्थियों की संख्या पांच लाख से कुछ ज्यादा ही है। अब तमिलनाडु में ऐसे लोग मिल जाएंगे, जो हिंदी के समर्थन में आवाज उठाते हैं। ऐसे लोगों में ज्यादातर वे हैं, जिन्होंने तमिलनाडु के बाहर भारतीयों के बीच संपर्क और संवाद के रूप में हिंदी को सहज पाया है और खुद हिंदी ना जानने की वजह से एक हद तक खुद को लाचार समझते रहे हैं। श्रीधर वेंबु जैसे लोगों का हिंदी के समर्थन में आना, ऐसी आवाजों को ताकत दे रहा है। यही ताकत तमिलनाडु में हिंदी के लिए उम्मीद की किरण है। यह ताकत तमिल उपराष्ट्रीयता के बेजा इस्तेमाल का भी जवाब है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

इसी भांति स्वधा शब्द का और तन्नामक कन्या का पितरों से सम्बन्ध प्रकट करना भी आलङ्कारिक एवं ऐतिहासिक दोनों पक्षों में श्लिष्ट होता है । इसलिये इस सन्दर्भ में इतिहास और धर्मतत्त्व का विमिश्रण स्पष्ट है।

राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस

सौरभ पोद्दार

देशभर में हर साल 6 मार्च को नेशनल डेंटिस्ट डे यानी राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दंत चिकित्सकों को उनके योगदान और मदद के लिए धन्यवाद देने के रूप में मनाया जाता है। दंत चिकित्सकों की मदद से ही लोगों की दांतों सी जुड़ी सारी परेशानी खत्म हो जाती है साथ ही लोगों की मुस्कुराहट और भी खूबसूरत हो जाती है। यह दिन लोगों को दांतों से जुड़े स्वास्थ्य के महत्व के बारें में अवगत कराने का खास मौके के रूप में मनाया जाता है।

नेशनल डेंटिस्ट डे हर साल 6 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन उन सभी डेंटिस्ट की प्रशंसा की जाती जो पूरी निष्ठा से अपना योगदान देते है। इन की वजह से ही लोगों की मुस्कुराहट और भी खूबसूरत हो जाती

है।

अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने साल 1938 में अपना 100वां वर्षगांठ मनाया था। इसके सम्मान में पहला नैशनल डेन्टिस्ट डे मनाया गया था। तब से अबतक हर साल 6 मार्च को नेशनल डेंटिस्ट डे मनाया जाता है।

इस दिन का खास महत्व होता है क्योंकि दंत चिकित्सकों की मेहनत और समर्पण की प्रशंसा की जाती है। कई जगहों पर दंत चिकित्सक हेल्थ चेकअप कैम्प या सेमिनार का आयोजन कराया जाता। हेल्थ चेकअप कैम्प या सेमिनार की मदद से डेंटिस्ट लोगों को जागरूक करते हैं कि वे अपने दांतों के हाइजीन का क्यों और कैसे ख्याल रखें साथ ही नियमित जांच के लिए डेंटिस्ट के पास जाने के लिए प्रेरित करते है। खासतौर से वैसे लोगों को जो अपने दांतों की जांच कराने से हिचकिचाते हैं।

तनाव से बुरा प्रभाव

तनाव का भी दांतों की सेहत पर बुरा असर होता है। दंत चिकित्सकों का मानना है कि तनाव के चलते कई लोग मदिरा पान और धूम्रपान शुरू कर देते हैं, जिसका सीधा असर भविष्य में दांतों पर पड़ता है। खट्टे व अम्लीय तरल पदार्थों के सेवन का असर भी दातों को प्रभावित करता है इसलिए बहुत कम मात्रा में इनका सेवन करना चाहिए। डॉक्टर्स बताते हैं कि फास्ट एवं रिफाइंड फूड का उपयोग बढ़ जाने से दूध के दांत भी समय से पहले गिर जाते हैं। दातों की इन समस्या को नजरअंदाज करने पर कई तरह की बीमारियां हो सकती है। इसके लिए समय-समय पर दातों की जांच करवानी चाहिए।

ऐसे करें दांतों की देखभाल

हल्के हाथों से दिन में दो बार दांतों के ऊपर और नीचे के हिस्से की सफाई करें।

शीतल पेय, डिब्बाबंद फलों के जूस, अधिक चीनीयुक्त भोजन और अम्लीय जूस का सीमित मात्रा में ही सेवन करें।

डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार हर छह महीने या साल में एक बार दांतों की सफाई जरूर कराए, इससे मसूड़े स्वस्थ और मजबूत रहेंगे।

यदि मसूड़ों में सूजन, खून आ जाए तो दंत चिकित्सक से परामर्श जरूर लेना चाहिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे बड़ा धमाका

नीरज कुमार दुबे

अमेरिका का राष्ट्रपति पद दोबारा संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह सरकार के खर्चों को कम करने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठा रहे हैं उस कड़ी में कुछ और कड़े कदम भी उठाये जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप के सहयोगी उनको इस बात के लिए मनाने में सफल होते दिख रहे हैं कि अमेरिका को नाटो और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक तथा आईएमएफ जैसे संस्थानों से भी बाहर निकल जाना चाहिए। हालांकि ट्रंप कोई भी फैसला करने से पहले तमाम मुद्दों पर विचार कर रहे हैं लेकिन वह इस बात के प्रबल पक्षधर हैं कि उनकी ओर से चलाये गये मागा अभियान के तहत देश को उन गठबंधनों या संस्थाओं से बाहर आना चाहिए जो अमेरिकी हितों का ख्याल नहीं करते हैं।

अमेरिकी अरबपति एलन मस्क जिन्हें अमेरिका के सरकारी खजाने से हो रहे फिजूलखर्च को रोकने के लिए बनाये गये सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) का प्रमुख बनाया गया है, उन्होंने सोशल मीडिया की जानी मानी हस्ती गुंथर ईगलमैन के उस सुझाव का समर्थन किया है जिन्होंने कहा था- यह नाटो और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) छोड़ने का समय है। इसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक संदेश के साथ रहस्य को और बढ़ा दिया, उन्होंने कहा, कल की रात बड़ी होगी।%% हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति मंगलवार रात को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं, जहां उनकी पार्टी के पास दोनों सदनों में बहुमत है।

हम आपको बता दें कि नाटो से बाहर आने के लिए तो अमेरिका में कई सांसदों की ओर से सार्वजनिक रूप से बयान भी दिये जाने लगे हैं। रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली ने नाटो को शीत युद्ध अवशेष के रूप में वर्णित करते हुए तर्क दिया है कि यह यूरोप को असंगत रूप से लाभ पहुंचाता है। माइक ली काफी समय से नाटो की आलोचना करते रहे हैं। वह कहते रहे हैं कि यह गठबंधन यूरोप के लिए एक बड़ा सौदा है लेकिन अमेरिका के लिए एक कच्चा सौदा है। उन्होंने हाल ही में एक्स पर लिखा था- हमें नाटो से बाहर निकालो। उन्होंने पिछले

महीने अन्य सांसदों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकलने का आग्रह किया गया था और इस वैश्विक संस्था को अत्याचारियों के लिए एक मंच और अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला करने का स्थान बताया गया था। इसके अलावा ट्रंप के वफादार माने जाने वाले मार्जोरी टेलर ग्रीन भी नाटो से अमेरिका की वापसी का आह्वान करने वालों में से हैं। हम आपको याद दिला दें कि ट्रंप ने पहले भी धमकी दी थी कि यदि अन्य सदस्य अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने में विफल रहे तो नाटो को रूसी बस के नीचे फेंक दिया जाएगा। उन्होंने एक बार चेतावनी देते हुए कहा था, वास्तव में, मैं उन्हें (रूस को) जो कुछ भी वे करना चाहते हैं उसे करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। आपको भुगतान करना होगा। आपको अपने बिलों का भुगतान करना होगा। ऐसी ही राय कई अन्य सांसदों, विधायकों ने भी व्यक्त की है। इस तरह देखा जाये तो अब एलन मस्क अमेरिका के नाटो सैन्य गठबंधन से बाहर निकलने के समर्थन में बयान देने वाले अकेले व्यक्ति नहीं रह गये हैं क्योंकि कई रिपब्लिकन सांसदों ने नाटो में अमेरिका की सदस्यता पर सवाल उठाया है, कुछ ने तो इस गठबंधन से तत्काल बाहर निकलने की मांग तेज कर दी है।

इस बीच, यह सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका नाटो से बाहर निकलने का विकल्प चुन रहा है? दरअसल एलन मस्क द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके लिए अपना समर्थन साझा करने के बाद हर कोई यही सवाल पूछ रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क की सलाह पर ध्यान दिया तो अमेरिका और दुनिया के लिए इसका क्या मतलब होगा? इन सवालों का जवाब देने से पहले नाटो के बारे में ट्रंप के रुख को समझना जरूरी है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सैन्य गठबंधन के आलोचक रहे हैं। जब वह पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े थे तब भी उन्होंने इस गठबंधन को अप्रचलित बताया था और अगस्त 2019 में तो उन्होंने यहां तक कहा था कि नाटो मर चुका है। अपने दूसरे कार्यकाल में भी ट्रंप नाटो के आलोचक रहे हैं। पद संभालने के कुछ ही दिनों बाद, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस गठबंधन के सदस्यों की रक्षा कर रहा था, लेकिन वे हमारी रक्षा नहीं कर रहे थे। उन्होंने नाटो सदस्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का पांच प्रतिशत रक्षा पर खर्च करने के लिए कहा। अभी नाटो सदस्य अपनी जीडीपी का दो प्रतिशत ही रक्षा पर खर्च करते हैं जिससे अमेरिका नाराज है। ट्रंप की शिकायत है कि अमेरिका अपने बजट से नाटो में बहुत अधिक योगदान देता है जबकि यूरोपीय संघ के सदस्य रक्षा पर बहुत कम खर्च करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका नाटो के वार्षिक बजट का लगभग छठा हिस्सा योगदान देता है।

अब सवाल उठता है कि क्या ट्रम्प नाटो और संयुक्त राष्ट्र से हट सकते हैं? इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ट्रंप ऐसा करते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कानूनी रूप से सिरदर्द पैदा हो जाएगा। दरअसल नाटो से बाहर निकलने के राष्ट्रपति के फैसले के लिए या तो दो-तिहाई सीनेट की मंजूरी होनी चाहिए या फैसले को कांग्रेस के एक अधिनियम के माध्यम से अधिकृत होना चाहिए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति चाहें तो इस नियम को दरकिनार कर सकते हैं लेकिन यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक बाध्यकारी संधि है, जिसमें स्वैच्छिक वापसी का कोई प्रावधान नहीं है। यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अमेरिका उन पांच देशों में शामिल है जिनको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाली स्थायी सदस्यता हासिल है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका वीटो पावर वाली सदस्यता को छोड़ना चाहेगा? सवाल यह भी उठता है कि क्या सदस्यता छोड़ने के बाद यदि अमेरिका पुनः इस विश्व संस्था में लौटा तो उसे आसानी से स्थायी सदस्यता और वीटो शक्ति फिर से मिल पायेगी? हम आपको यह भी बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के इतिहास पर नजर डालने से पता चलता है कि मलेशिया के सुरक्षा परिषद में चुने जाने के विरोध में 1965-66 तक संयुक्त राष्ट्र से हटने वाला इंडोनेशिया एकमात्र देश था। हालाँकि, वे 1966 में वापस आ गए थे।

इसके अलावा यदि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकलता है तो इससे इस विश्व निकाय की फंडिंग पर भी असर पड़ेगा क्योंकि अमेरिका ही इस संस्था का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र से ट्रंप का हटना अमेरिका के उन सिद्धांतों को भी नष्ट कर देगा जिसके चलते अमेरिकी भूमि पर ही इस संस्था की स्थापना की गयी थी। हम आपको यह भी बता दें कि ट्रंप प्रशासन पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से हट चुका है, जिसका असर वैश्विक स्वास्थ्य पर पड़ा है।

इसके अलावा, यदि अमेरिका नाटो और संयुक्त राष्ट्र से बाहर आ जाता है तो इसके प्रभाव स्वरूप यूरोप तुरंत संभावित रूसी हमले के निशाने पर आ जायेगा। इसके अलावा यूक्रेन के लिए रक्षा आपूर्ति पूरी तरह खत्म हो जाएगी और उसके समक्ष रूस के साथ संघर्षविराम की स्थिति नहीं बल्कि आत्मसमर्पण की परिस्थिति होगी। इसके अलावा, अमेरिका के नाटो छोड़ने की संभावना कई यूरोपीय देशों को अपने सैन्य संसाधनों पर बेशुमार खर्च बढ़ाने के लिए मजबूर कर देगी। वहीं, यदि अमेरिका ने नाटो को छोड़ दिया तो इससे अमेरिका को यह नुकसान होगा कि यूरोप, अफ्रीका या पश्चिम एशिया में उसकी उपस्थिति नहीं रहेगी और दुनिया भर में कई सैन्य अड्डों तक उसकी पहुँच खत्म हो सकती है। इससे अमेरिका को यह भी नुकसान होगा कि कई देश रूस या चीन के करीब आ जायेंगे।

बहरहाल, देखना होगा कि अपने सहयोगियों के सुझावों पर ट्रंप क्या फैसला लेते हैं। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि यदि अमेरिका नाटो, संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ या विश्व बैंक से बाहर निकलता है तो वह निश्चित रूप से वैश्विक मामलों पर अपनी पकड़ खो देगा और चीन को सशक्त बना देगा। वैश्विक संस्थाओं से अमेरिका की वापसी तमाम देशों को चीन की कक्षा में धकेल देगी, जिससे दुनिया में अमेरिका की बादशाहत कम हो जायेगी।

आज का इतिहास

1886 नर्सों की पहली पत्रिका नाइटिन्गेल प्रकाशित हुई।
1900 वेस्ट वर्जीनिया, यू.एस.ए. में हुए एक कोयला खान विस्फोट में 50 खनिक मारे गए।
1902 स्पेन में मैड्रिड क्लब की स्थापना हुई।
1902 रियल मैड्रिड, दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉल (सॉकर) क्लब, मैड्रिड फुटबॉल क्लब के रूप में था।
1902 रियल मैड्रिड सी.एफ. फुटबॉल क्लब के रूप में स्थापित हुआ।
1913 प्रथम बाल्कन युद्ध-यूनानी सेना ने ओटोमन से बिज़नी किले को निकट इओनिनीना पर कब्जा कर लिया।
1921 पुर्तगाली कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई।
1930 कम्युनिस्ट इंटरनेशनल द्वारा आयोजित, दुनिया भर के प्रमुख शहरों में सैकड़ों हज़ारों लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन से जुड़े सामूहिक बेरोजगारी के विरोध में मार्च किया।
1945 प्लोमेनस फ्रंट के पेत्रु ग्रोज़ा, रोमानिया की कम्युनिस्ट पार्टी-वर्चस्व वाली सरकारों के पहले प्रधानमंत्री बने।
1960 स्विट्जरलैंड ने स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया।
1964 एक रेडियो प्रसारण में, नेशन ऑफ इस्लाम के नेता एलिजा मुहम्मद ने बताया कि अमेरिकी मुक्केबाज कैसियस क्ले अपना नाम बदलकर मुहम्मद अली रखेंगे।
1964 कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय अपने पिता राजा पॉल की मृत्यु के बाद ग्रीस के राजा बने।
1971 स्विट्जरलैंड के बुर्गोल्ज़ली शहर के एक मानसिक अस्पताल में आग लगने से 28 लोग मारे गए।
1975 पहली बार टेलीविज़न पर जॉन एफ. कैनेडी की हत्या की ज़ेरुडर फिल्म।
1975 ईरान और इराक ने एक सीमा विवाद को निपटाने के लिए अल्जीयर्स समझौते पर हस्ताक्षर किए, केवल पांच साल बाद फिर से लड़ना शुरू करने के लिए -इराक-इराक युद्ध।
1981 अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 37000 संघीय नौकरियों में कटौती करने की घोषणा की।
1984 ब्रिटिश कोयला उद्योग में एक साल की लंबी कार्रवाई शुरू हुई।
1988 ऑपरेशन फ्लेवियस में, ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस ने तीन प्रोविजनल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के स्वयंसेवकों को मार डाला, जब वे जिब्राल्टर में ब्रिटिश सैन्य बैंड की परेड पर बमबारी करने की साजिश रच रहे थे।
1994 कॉलिन जैक्सन ने 60 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने सिर्फ 4.30 सेकंड में 60 मीटर की दौड़ पूरी की।
1996 ईराक ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत खाद्य के लिये तेल योजना को स्वीकार किया, आयरिश रिपब्लिक आर्मी ने त्वरित युद्ध विराम को नकारते हुए ब्रिटेन के साथ 25 वर्षीय युद्ध की घोषणा की।

बसपा की सियासी दुर्गति के लिए मायावती अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर क्यों थोप रहीं?

कमलेश पांडे

उत्तरप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की नेत्री सुश्री मायावती भले ही दलित की बेटी हैं, लेकिन जब दलित राजनीति के रथ पर सवार होकर वह सूबाई सत्ता और पार्टी दोनों के शीर्ष तक पहुंचीं तो दौलत पसंद बन गईं। उन्होंने अपनी सारी नीतियों को दौलत बटोरने के ही इर्दगिर्द केंद्रित कर दिया। जिससे दृढ़ स्वभाव की इस महिला नेत्री ने न केवल अकूत धन बटोरीं, बल्कि अपनी पार्टी को भी खूब आगे बढ़ाया। इस क्रम में उन्होंने जायज-नाजायज का ख्याल तक नहीं रखा। क्योंकि दलित समर्थक एक कानून हमेशा उन जैसों की कानूनी ढाल बन जाता है। हालांकि, वक्त का पाशा पलटते ही अब वही दौलत उन जैसी अविवाहित महिला के गले की फांस बन चुका है।

कहना न होगा कि जिस बामसेफ ने देश की दलित राजनीति को एक मजबूत प्रशासनिक आधार दिया, उसकी भी मायावती काल में इसलिए एक न चली, क्योंकि परिवार और पार्टी से आगे की सोच-समझ उनमें विकसित ही न हो पाई। दरअसल, बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम के मेहनत से फली-फूली धुर ब्राह्मण विरोधी दलित पार्टी बसपा पर मायावती ने उनके जीते जी ही अपना कब्जा जमा लिया और अपने सहोदर भाई आनंद की मदद से निरंतर मजबूत होती चली गईं, लेकिन जब से उन्होंने सत्ता प्राप्ति की गरज से ब्राह्मणों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर विकसित किया, तब से उन्हें अप्रत्याशित राजनीतिक सफलता तो खूब मिली, लेकिन उनका मूल कैडर इधर उधर छिटकने लगा।

इसके अलावा, जब से समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव से उनकी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भाजपा नेताओं की शह पर तेज हुई, तब से दलित समर्थक ओबीसी भी उनसे छिटकने लगे। वहीं, भाजपा के समर्थन से सत्ता की राजनीति जबसे उन्होंने शुरू की, तब से मुस्लिम वोटर भी बसपा से दूरी बनाने लगे। हालांकि, सत्ता संतुलन के लिए उन्होंने सवर्णों, ओबीसी और अल्पसंख्यक नेताओं को मलाईदार पद दिए, जिससे दलित भी उनसे ईर्ष्या करने लगे। इन सब कारणों से बसपा का जनाधार छीजता चला गया।

वहीं, कभी भाजपा, कभी समाजवादी पार्टी, कभी कांग्रेस और कभी अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की राजनीति करके उन्होंने खुद को तो मजबूत बनाने की पहल की, लेकिन उनकी अड़ियल और हठी रवैये के चलते उनकी पटरी किसी से नहीं बैठी और अब राजनीतिक मजबूरी वश वह बिल्कुल अकेले बच गई हैं। सवाल है कि तीन बार भाजपा या सपा के सहयोग से और एक बार अपने दम पर हासिल बहुमत से यूपी की मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती, केंद्रीय राजनीति में अपने अच्छे-खासे सांसदों के बल पर दबदबा रखने वाली मायावती आखिर इस सियासी दुर्दिन को कैसे प्राप्त हुईं।

तो जवाब यही होगा कि एक ओर उनका पारिवारिक प्रेम और दूसरी ओर भावनात्मक रूप से जुड़े नेताओं-कार्यकर्ताओं की मौद्रिक कारणों से उपेक्षा। हालांकि, जब तक वह इस बात को समझ पाई, तबतक बहुत देर हो चुकी है। आज उनके सांसदों और विधायकों की संख्या न के बराबर है। ऐसे में उनके घर में और पार्टी में जो पारिवारिक कोहराम मचा हुआ है, वह कोई नई बात नहीं है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं।

हालांकि, यह भी कड़वा सच है कि अपनी जिस जिद्दी स्वभाव के चलते वह सियासत में खूब आगे बढ़ीं, अब उसी जिद्दी स्वभाव के चलते उनकी पार्टी और परिवार दोनों बिखराव के कगार पर है। वहीं, 70 वर्षीय मायावती सूझबूझ से काम लेने के चक्कर में गलतियां पर गलतियां करती जा रही हैं। जिस तरह से वो अपने ही निर्णय को बार बार पलट देती हैं, उससे उनकी सियासी साख भी चौपट हो रही है। इससे सीएम-पीएम बनने का उनका ख्वाब तो चूर हो ही रहा है, लेकिन जोड़-तोड़ से राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनने या फिर केंद्रीय मंत्री बनने की बची खुची संभावनाएं भी समाप्त होती जा रही हैं।

चूंकि देश की दलित राजनीति का यह दुर्भाग्य रहा है कि ओबीसी नेताओं की तरह ही दलित नेता भी एक दूसरे राज्यों के बड़े दलित नेताओं से स्वभाविक समझदारी विकसित नहीं कर पाए और खुद को कमजोर करते चले गए। यूपी में तो मायावती ने दलितों को कद्दावर मुख्यमंत्री दिया, लेकिन बिहार आजतक उससे वंचित है। शायद इसलिए कि भाजपा-कांग्रेस ने अपनी सियासी हितों के लिए इन्हें भी आपस में लड़ाया और अपने इरादे में कामयाब रहे। काश! मायावती भी यह सबकुछ समझ पातीं और तदनुसार निर्णय लेतीं।

हाल ही में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद

को हटाते हुए उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ पर जो निशाना साधा निशाना है, इससे उन्हें लाभ के बजाय और अधिक हानि हो सकती है, क्योंकि ये पार्टी के मजबूत स्तंभ रहे हैं और उनकी हर कमजोरी से वाकिफ हैं। यदि ये विभीषण बन गए तो उनका क्या होगा, सोच-समझ लें तो उचित रहेगा। दरअसल, मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है लेकिन इसके लिए उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को ज़िम्मेदार ठहराया है।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक समेत सभी अहम पदों से हटा दिया और कहा कि अहम फ़ैसले अब वह खुद लेंगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक वह ज़िंदा रहेंगी, तब तक उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि उनके लिए पार्टी पहले है और बाकी रिश्ते-नाते बाद में। बता दें कि 2019 में मायावती ने आकाश को पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक बनाया था और अपने छोटे भाई यानी आकाश के पिता आनंद कुमार को बीएसपी का उपाध्यक्ष बनाया था।

इसके बाद से ही मायावती पर भाई-भतीजावाद के आरोप लग रहे थे। ऐसे आरोप पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह लग रहे थे। कई लोग यह भी कहते हैं कि पार्टी के पुराने नेता आकाश आनंद को लेकर बहुत सहज नहीं थे। ऐसे में दिलचस्प है कि अब आकाश आनंद की जगह उनके पिता आनंद कुमार और साथ में रामजी गौतम को राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया है। साथ ही अपने भतीजे को सभी अहम पदों से हटाने के फ़ैसले को सही ठहराते हुए मायावती ने बीएसपी के संस्थापक कांशीराम का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि कांशीराम पार्टी में परिवार और रिश्तेदारों के काम करने के खिलाफ़ नहीं थे लेकिन उन्हें बाक़ी कार्यकर्ताओं से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले, इसके ख़िलाफ़ थे।

ऐसे में सवाल है कि मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को बीएसपी से क्यों निकाला था? क्या पारिवारिक कलह से जूझ रही हैं पार्टी सुप्रीमो? ऐसे में मायावती के भतीजे आकाश आनंद क्या उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बन पाएँगे? क्योंकि मायावती के पुराने तेवरों की वापसी से मिलते नए संकेत से पता चलता है कि इसका भावी असर क्या होगा? ये तो वही जानें।

दरअसल, लखनऊ में रविवार को बीएसपी की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि कांशीराम के पदचिह्नों पर चलते हुए ही आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया है और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया गया है। अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी को पूरे देश में दो गुटों में बाँटकर कमज़ोर किया है। बीएसपी ने कहा है कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकालने के बाद यह देखना होगा कि उनकी लड़की यानी आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा पर इसका क्या असर पड़ता है और यह भी देखना होगा कि पत्नी का प्रभाव आकाश पर कितना पड़ता है। बीएसपी का कहना है कि इस आकलन पहले कुछ भी सकारात्मक नहीं लग रहा है।

पार्टी का कहना है कि आकाश आनंद के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई, उसकी ज़िम्मेदारी उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की बनती है। क्योंकि अशोक सिद्धार्थ के कारण ही पार्टी का तो नुक़सान हुआ ही है, आकाश आनंद का राजनीतिक करियर भी ख़राब हो गया है। मायावती ने यह भी कहा है कि अशोक सिद्धार्थ से मिले सबक के बाद आनंद कुमार ने अब अपने बच्चों का रिश्ता ग़ैर-राजनीतिक परिवार में जोड़ने का फ़ैसला किया है, ताकि बीएसपी के आंदोलन पर नकारात्मक असर ना पड़े।

बता दें कि अशोक सिद्धार्थ भी बीएसपी और मायावती के लिए कोई अनजाने व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि मायावती के वफ़ादरों में अशोक सिद्धार्थ का नाम पहली पंक्ति में आता था। लेकिन गत 12 फ़रवरी 2025 को मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि दक्षिणी राज्यों के प्रभारी डॉ अशोक सिद्धार्थ चेतावनी के बावजूद गुटबाजी में लगे थे। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया है। इस पर मायावती ने कहा कि मान्यवर कांशीराम के पद चिन्हों पर चलकर मैं भी एक ईमानदार व निष्ठावान शिष्या और उत्तराधिकारी के नाते अशोक सिद्धार्थ को आंदोलन के हित में पार्टी से बाहर कर दिया है। इसके बाद से उनके परिवार का अंतर्कलह और बढ़ गया।

दरअसल, अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा सिद्धार्थ से ही आकाश की शादी 2023 में हुई थी। तब अशोक सिद्धार्थ को बीएसपी में मायावती के बाद दूसरी पंक्ति के अहम नेता के रूप में देखा जाता था। क्योंकि मायावती ने ही अशोक सिद्धार्थ को राज्यसभा भी भेजा था और दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार की ज़िम्मेदारी दी थी। मायावती से संबंधों में भरोसे के कारण ही मार्च 2023 में अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा और आकाश आनंद की शादी हुई थी। कहा जाता है कि आकाश को दोबारा राष्ट्रीय समन्वयक बनाने में अशोक सिद्धार्थ की अहम भूमिका थी।

वहीं, बीएसपी में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और अशोक सिद्धार्थ के बीच काफी तनातनी की ख़बरें पहले से ही आ रही थीं। जिसके चलते ही अशोक सिद्धार्थ को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीएसपी कैंपेन का प्रभारी बनाया गया था लेकिन वहां भी पार्टी औंधे मुँह गिरी थी। ऐसे में सवाल है कि अब आकाश आनंद का क्या होगा, क्योंकि आकाश आनंद को दूसरी बार बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटाया गया है। ऐसे में अब सुलगता सवाल यही है कि क्या आकाश आनंद का बीएसपी में भविष्य ख़त्म हो गया है?

हालांकि आकाश की जगह उनके पिता को ज़िम्मेदारी देने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है कि उनका भविष्य ख़त्म हो गया है। क्योंकि मायावती क़रीब 70 साल की हो गई हैं और पार्टी को एक नौजवान नेता चाहिए। ऐसे में आकाश आनंद को भले अभी नेपथ्य में रख रही हैं लेकिन आख़िरकार पार्टी की कमान परिवार के हाथों में ही आएगी। लेकिन चिंता की बात यह है कि पार्टी पिछले डेढ़ दशक में काफ़ी कमज़ोर हुई है। पार्टी का जनाधार तेज़ी से गिरा है और अभी इस बात के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं कि बीएसपी अपना खोया जनाधार वापस पा लेगी। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में 488 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी।

अपने मतलबी आकाओं से सचेत रहें मुस्लिम

वकील अहमद

इस समय देश में मुस्लिम समुदाय का ज्यादातर हिस्सा चिंतित व परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को अधिकतर मुसलमान मुसलमानों के खिलाफ मानते हैं कि भाजपा सरकार निरंतर मुसलमानों के मामले में उनके धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ कर रही है और भी न जाने क्या-क्या धारणाएं भाजपा सरकार के बारे में मुस्लिमों के दिल में घर कर रही हैं। निस्संदेह भाजपा ऊपरी तौर पर ऐसा दिखाकर कि वह मुस्लिमों के लिए गंभीर नहीं है, राजनीतिक लाभ उठा रही है। ठीक उसी तरह जैसा कभी कांग्रेस मुस्लिमों को सिर्फ दिखावे के नाम पर गोद में बैठाए रहती थी लेकिन उनके कल्याण के लिए कभी कुछ किया नहीं। दरअसल मुस्लिमों को आश्रित रहने की आदत हो गई है। पहले उन्हें कांग्रेस ने अपने ऊपर आश्रित रखा फिर कांग्रेस से उनका मोह भंग हुआ तो इस कारण नहीं कि कांग्रेस ने उनके लिए कुछ नहीं किया बल्कि बाबरी ढांचे के गिरने के बाद उनका कांग्रेस से मोह भंग हुआ। फिर वह राज्यों क्षत्रपों के अपने हितों के लिए उनके साथ हो लिए जैसे उ.प्र. में उन्हें मुलायम सिंह इसलिए पसंद नहीं थे कि उन्होंने उनके कल्याण के काम किए बल्कि वह इसलिए पसंद थे कि उन्होंने अयोध्या में गोली चलवाई, चंद गुंडा तत्व और दबंग मुस्लिमों को नेता बना दिया। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वह धर्म के मामले में बेहद संवेदनशील हैं। उन्हें अपनी उन्नति से ज्यादा धार्मिक चिंताएं हैं इसी का फायदा उठाकर उनके तथाकथित ठेकेदार जो कहीं उलेमा के रूप में और कहीं नेता के रूप में उनकी इस कमजोरी के कारण उनका लाभ उठाते रहते हैं। उन्हें समझाने की बजाय उल्टा भड़काते हैं। भाजपा सरकार तीन तलाक कानून लाई, यह कानून मुस्लिम महिलाओं के हित में था। इसके लिए भी माहौल बनाया गया कि भाजपा हमारे धार्मिक मामलों में दखल दे रही है। ऐसा करने वाले लोगों को समझ नहीं आया कि इससे उन महिलाओं को कितनी राहत मिलेगी जिनके सिर पर तीन शब्दों की तलवार लटकी रहती है। कम से कम वह इसके खिलाफ अदालत में तो जा सकेगी। ऐसे ही वक्फ बोर्ड की बात है। वक्फ बोर्ड के पास कितनी सम्पत्ति है। पहले तो आम लोगों को ही इसका नहीं पता। सरकार इसमें पारदर्शिता लाना चाहती है तो विरोध किया जाता है। दरअसल यह विरोध मुस्लिम जनता स्वयं नहीं करती। उनके आकाओं के पेट में दर्द होता है तो वह उन्हें भड़काते हैं। मैं समझता हूं कि क्या वक्फ सम्पत्तियों का लाभ मुसलमानों को मिला, उन पर कितने कालेज और कितने अस्पताल बने जबकि कोई वक्फ को सम्पत्ति दान करता है तो वह लोगों के हित में काम आ सके इसलिए करता है लेकिन उसका बंदरबाट होता है। समान नागरिक संहिता की जहां तक बात है, उसका अर्थ हर धर्म समाज के लिए एक ही तरह का कानून हो यह सही भी है। देश के कानून में धर्म के कानूनों का घालमेल करोगे तो विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के देश में यह संभव नहीं हो सकता। दरअसल मुसलमानों को यह बात समझनी होगी कि उनके जो भी आका हैं उनका वह लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में चल रहे अनगिनत मदरसे जहां मुस्लिम युवा दीनी तालीम लेकर धर्म के ज्ञाता तो बन जाते हैं मगर आगे नहीं बढ़ पाते। ये मदरसे चंद लोगों की कमाई का जरिया है।

कहीं एम.के. स्टालिन पर उल्टा न पड़ जाए हिंदी विरोध!

विनोद पाठक

तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। राज्य में कोई भी बड़ा मुद्दा अपने पक्ष नजर नहीं देख द्रमुक पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बार फिर हिंदी विरोध के मुद्दे को चुना है। यह विरोध हिंदी का नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक एजेंडा भर दिख रहा है। तमिलनाडु में भी अन्य राज्यों की तरह सत्ता विरोधी लहर चलती है।

हर पांच साल बाद जनता अक्सर सरकार बदल देती है। एम.के. स्टालिन के पक्ष में परिस्थितियां अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। यही कारण है कि उन्होंने वर्ष 1937 से चले आ रहे हिंदी विरोधी मुद्दे को विधानसभा चुनाव से सालभर हवा देना प्रारंभ कर दिया है। हालांकि, यह लग रहा है कि इस बार उनका यह पैंतरा चलने वाला नहीं है।

आपको थोड़ा सा अतीत में लेकर चलता हूं। सितंबर 2020 में एम.के. स्टालिन की बहन और द्रमुक पार्टी नेता कनिमोझी ने हिंदी विरोध में चुनाव से पहले यूं ही झंडा बुलंद किया था। उस समय बात यहां तक पहुंच गई थी कि कनिमोझी ने तत्कालीन केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक को चिट्ठी लिखकर तब मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटोचा का इस्तीफा तक मांग लिया था, क्योंकि कनिमोझी का

आरोप था कि कोटेचा ने एक वेबीनार में हिंदी नहीं जानने वाले प्रतिभागियों को सत्र छोड़कर जाने के लिए कहा था।

कनिमोझी ने चेन्नई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवान पर उन्हें हिंदी को लेकर तंग करने का आरोप लगाया था, जो असत्य निकला था। कनिमोझी ने यहां तक कहा था कि उन्हें हिंदी आती नहीं है, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके उल्ट है। कनिमोझी को न केवल हिंदी अच्छे से आती है, बल्कि उर्दू, तमिल, अंग्रेजी समेत पांच भाषाओं को वो जानती हैं।

आपकी स्मृति के लिए बता दूं। एक बार पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल चेन्नई पहुंचे थे। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि की मौजूदगी में हिंदी में भाषण दिया था। तब उनके हिंदी भाषण का तमिल में रूपांतरण कनिमोझी ने किया था। अब आप समझ लीजिए, हिंदी को लेकर कनिमोझी का विरोध कैसा था?

अब एम.के. स्टालिन पर आते हैं। स्टालिन अब केवल हिंदी का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि वो इससे आगे बढ़कर संस्कृत तक पहुंच गए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि संघ परिवार का असली एजेंडा संस्कृत को थोपने का है। हिंदी को लेकर उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि हिंदी के कारण यूपी-बिहार में 25 से ज्यादा भाषाएं खत्म हो गईं हैं।

यह रिसर्च स्टालिन ने कब कराई? यह उन्होंने बताया नहीं है। साफ दिख रहा है कि स्टालिन एक बार फिर भाषा के आधार पर भावनाओं को भड़का कर वोट लेने की मंशा रखते हैं। संभवत: पिछले 4 सालों में उन्होंने क्या काम कराए हैं, यह बताने के लिए नहीं है। इसलिए राजनीति अब हिंदी-संस्कृत पर आकर रुक गई है।

आखिर एक नई भाषा को सीखने में हर्ज क्या है? क्या तमिलनाडु के युवाओं को हिंदी नहीं आनी चाहिए? यदि अवसर मिले तो हिंदी भाषी युवा भी तमिल सीखना चाहेगा। आज हिंदी बोलने वालों की संख्या दुनिया में 70 करोड़ से अधिक है। भारत में ही 53 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी का बहुत बड़ा बाजार है। हिंदी की मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है।

ऐसे में किसी एक राज्य के युवाओं को हिंदी जैसी भाषा से राजनीतिक कारणों से दूर करना कितना उचित है? फिर नई शिक्षा नीति-2020 में कहीं भी यह बाध्यता नहीं है कि आपको हिंदी सीखनी ही है। किसी दूसरी भारतीय भाषा को भी तमिलनाडु के युवा सीख सकते हैं। साफ है कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जानबूझकर हिंदी का ही विरोध कर रहे हैं। मातृभाषा में पढ़ाई और अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा में पढ़ाई हो ही रही है।

यह भी सत्य है कि तमिलनाडु में भाजपा धीरे-धीरे अपना वोटबैंक बढ़ा रही है। इस समय द्रमुक के आगे बड़ी चुनौती यह है कि भाजपा का मत प्रतिशत तमिलनाडु में बढ़ रहा है। अगर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो डीएमके को 46.9त्न वोट मिले, जो वर्ष 2019 के मुकाबले 6.18त्न कम थे, जबकि एआईएडीएमके ने 23.05त्न हासिल किए, जो पिछले चुनाव से 1.50त्न ज्यादा थे। भाजपा ने 18.28त्न वोट हासिल किए, जो पिछले चुनाव से 3.31त्न अधिक थे। के.अन्नामलाई के नेतृत्व में भाजपा इस समय बहुत आक्रमक तरीके से तमिलनाडु में प्रचार कर रही है।

एआईएडीएमके की चुनौती तो शुरू से द्रमुक के आगे रही है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का हिंदी-संस्कृत विरोध कहां तक जाता है? हिंदी को लेकर इंडी गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस का क्या रुख रहता है? यह भी संभव है कि इस बार हिंदी विरोध को वो समर्थन न मिले, जैसा पहले मिलता था। कहीं एम.के. स्टालिन का हिंदी विरोध उन पर उल्टा न पड़ जाए।

भारत में भ्रष्टाचार है बेलगाम

राज कुमार सिंह

भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के वायदे वफा होते नजर नहीं आते। दुनिया भर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करने वाली गैर-सरकारी संस्था ट्रांसपेरैंसी इंटरनैशनल की नई रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए नारे कि 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' के बावजूद भारत में भ्रष्टाचार बेलगाम है। कारोबारियों के साथ-साथ राजनेताओं और नौकरशाहों के यहां से भी छापों में भारी नकदी की बरामदगी का अर्थ यही है कि खाने-खिलाने का सिलसिला बंद तो नहीं हुआ है। ट्रांसपेरैंसी इंटरनैशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सी.पी.आई. पर आधारित वर्ष 2024 के लिए हाल ही में जारी भ्रष्ट देशों की सूची बताती है कि भ्रष्टाचारमुक्त भारत सपना ही बना हुआ है। इस सूची में शामिल 180 देशों में भ्रष्टाचार के मामले में भारत 38 अंकों के साथ 96वें स्थान पर है, जबकि साल 2023 में भारत 39 अंकों के साथ 93वें स्थान पर था। दरअसल जिस देश को सी.पी.आई. में ज्यादा अंक मिलते हैं, वहां भ्रष्टाचार कम माना जाता है।

घटते अंक ज्यादा भ्रष्टाचार का प्रमाण होते हैं, जिनके साथ-साथ सूचकांक में देश की रैंकिंग भी बढ़ती जाती है। हमारे देश में भ्रष्टाचार अक्सर राजनीतिक मुद्दा बन कर रह जाता है। इसलिए यह जानना भी जरूरी है कि वर्तमान मोदी सरकार और पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार के शासनकाल में

भ्रष्टाचार के मोर्चे पर भारत का प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से कैसा रहा। ट्रांसपेरैंसी इंटरनैशनल द्वारा हर साल जारी की जाने वाली भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आधारित 180 देशों की सूची बताती है कि पिछले 10 सालों में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। पिछले 10 सालों में इस सूची में भारत ने सबसे बेहतर प्रदर्शन साल 2015 में किया था जब उसे रैंकिंग में 76वां स्थान हासिल हुआ था। वैसे साल 2006 और 2007 में भारत क्रमशः 70वें और 72वें स्थान पर भी रहा यानी दोनों ही सरकारों के आरंभकाल में भ्रष्टाचार कम होता नजर आया पर फिर बेलगाम हो गया। हमारा पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी देश चीन 43 अंकों के साथ 76वें स्थान पर बना हुआ है।

हमारे नीति नियंता इस बात पर संतोष जता सकते हैं कि पड़ोसी देशों में पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे भी खराब है। साल 2023 में पाकिस्तान 29 अंकों के साथ 113वें स्थान पर था लेकिन बीते साल वह 27 अंकों के साथ 135वें स्थान पर पहुंच गया। इस सूची में श्रीलंका और बंगलादेश की रैंकिंग बता कर भी हमारे सत्ताधीश अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। बीते साल इस सूची में श्रीलंका 121वें और बंगलादेश 149वें स्थान पर है, लेकिन हमारे पड़ोस में तो छोटा-सा देश भूटान भी है। भ्रष्ट देशों की रैंकिंग में 18वें नंबर पर रहा भूटान दुनिया के खुशहाल देशों में भी गिना जाता है। जाहिर है, वायदों और दावों के विपरीत वास्तविकता हमारी व्यवस्था और मानसिकता पर सवाल खड़े करती है, जिसके जवाब खोजे बिना हम विश्व की तीव्र वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था भले बन जाएं बेहतर देश नहीं बन पाएंगे। आर्थिक प्रगति में आंकड़ों के महत्व से इंकार नहीं है, लेकिन राष्ट्र की असली प्रगति समाज के सर्वांगीण विकास और खुशहाली में होती है।

लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो राशन मुफ्त देने की जरूरत देश की खुशहाली का प्रमाण तो हर्गिज नहीं। बढ़ती बेरोजगारी तथा शिक्षा स्वास्थ्य की बदहाल व्यवस्था भी वास्तविक विकास के दावों पर सवालिया निशान है। इसलिए हमें आंकड़ों पर आधारित आर्थिक प्रगति पर आत्ममुग्धता से उभर कर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पर आधारित इस सूची में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों से जरूरी सबक भी सीखने होंगे। 90 अंकों के साथ डेनमार्क इस सूची में सबसे ऊपर है, जिसका अर्थ है कि वहां नाममात्र का ही भ्रष्टाचार है। 88 अंकों के साथ फिनलैंड इस सूची में दूसरे स्थान पर है, जिसे विश्व का सबसे खुशहाल देश भी माना जाता है। 84 अंकों के साथ सिंगापुर तीसरे, 83 अंकों के साथ न्यूजीलैंड चौथे और 81 अंकों के साथ लग्जमबर्ग पांचवें स्थान पर है।

महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अब विदेश में बसने के इच्छुक भारतीय इन छोटे देशों को भी अपना गंतव्य बनाने लगे हैं। क्या यह बात का संकेतक नहीं कि ये देश उन्हें हर दृष्टि से बेहतर जीवन स्तर का विकल्प नजर आते हैं। बेशक सबसे भ्रष्ट देशों की सूची पर नजर डालना भी जरूरी है। 8 अंकों के साथ दक्षिण सूडान 180 देशों में सबसे भ्रष्ट देश है जबकि सोमालिया और वेनेजुएला 9 और 10 अंकों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे भ्रष्ट देश हैं। उनके बाद सीरिया, लीबिया, इरिट्रिया, यमन और इक्वेटोरिल गिनी का नंबर आता है। वैसे इस सूची में रूस, अमरीका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे प्रभावशाली देश क्रमशः 154वें, 28वें, 25वें, 20वें और 15वें स्थान पर हैं। ट्रांसपेरैंसी इंटरनैशनल के मुखिया फ्रैंकोइस वेलेरियन कहते हैं कि भ्रष्टाचार एक उभरता हुआ वैश्विक खतरा है, जो विकास को रोकता है। साथ ही यह लोकतंत्र में गिरावट, अस्थिरता और मानवाधिकारों के उल्लंघन को भी बढ़ाता है। कहना नहीं होगा कि ज्यादा भ्रष्टाचार वाले देश इन तमाम खतरों से रू-ब-रू हैं। यह भी कि इन खतरों से निपटे बिना देश और समाज के सर्वांगीण विकास के दावे संदेह और सवालों में ही घिरे रहेंगे।

जस्टिस गवई की एक गलती

जूलियो रिबैरो

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस बी.आर. गवई निकट भविष्य में कुछ समय के लिए मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर आसीन होंगे। गवई महाराष्ट्र के विदर्भ जिले से आने वाला एक प्रसिद्ध और सम्मानित परिवार है। गवई आर.पी.आई. (रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया) में प्रमुख थे। जब पार्टी दो गुटों में विभाजित हो गई तो एक गुट का नेतृत्व इस परिवार ने किया। इस पृष्ठभूमि के प्रकाश में जस्टिस गवई को गरीबों और वंचितों का दुश्मन मानना मुश्किल है। रिपब्लिकन पार्टी डा. आंबेडकर के अनुयायियों की पार्टी थी। बॉम्बे (अब मुंबई) में एक युवा छात्र के रूप में मुझे याद है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आर.पी.आई. उम्मीदवारों के समर्थन में आर.पी.आई.समर्थकों को ले जाने वाले कई खुले ट्रक मेरे बायकुला स्थित घर के पास से गुजरते थे।

फिर भी, संविधान आचरण समूह (सी.सी.जी.) में अपने मित्रों और सहकर्मियों के साथ मैंने न्यायमूर्ति गवई को अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र भेजा जिसमें हमने अपनी सामूहिक निराशा व्यक्त की क्योंकि उन्होंने इस वर्ष 12 फरवरी को एक सिविल रिट याचिका की सुनवाई करते हुए बेघर लोगों के लिए 'परजीवी' शब्द का इस्तेमाल किया था जिसमें उनके लिए पर्याप्त आश्रय सुविधाओं का अनुरोध किया गया था। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गवई ने निम्नलिखित मौखिक टिप्पणी की। दुर्भाग्य से, इन लोगों को मुख्यधारा के समाज का हिस्सा न बनाकर क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं? चुनाव घोषित होने पर मुफ्त सुविधाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं होते हैं। उन्हें बिना कोई काम किए मुफ्त राशन मिल रहा है। क्या उन्हें मुख्यधारा के समाज का हिस्सा बनाना बेहतर नहीं होगा ताकि वे राष्ट्र के लिए योगदान दे सकें।

रोमानिया जैसे कम्युनिस्ट देश में, जहां मैं 4 साल तक रहा, कुसेस्कु शासन ने अपने सभी नागरिकों के बीच गरीबी फैला दी थी। हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार नौकरी दी जाती थी और न्यूनतम वेतन दिया जाता था जो भोजन, कपड़े और आवास पर होने वाले खर्चों को पूरा करता था। बेशक नोमेनक्लातुरा और सरकारी अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए आवास के स्तर में अंतर था।उस व्यवस्था को अधिकांश आबादी ने पसंद नहीं किया। इस तरह के आदेश केवल कम्युनिस्ट शासन में प्रचलित शासन के नियमित रूप में ही लागू किए जा सकते थे। मुझे नहीं लगता कि जस्टिस गवई हमारी बेरोजगारी और गरीबी की समस्या के लिए इस तरह के समाधान के बारे में सोच रहे थे। अच्छे जज की टिप्पणियों पर अधिकांश टिप्पणियां उनके द्वारा 'परजीवी' शब्द के इस्तेमाल पर केंद्रित थीं। जस्टिस गवई ने गलत शब्द चुना और मुझे यकीन है कि उन्हें अब तक यह एहसास हो गया होगा। उनके असली विलाप का अंदाजा उनके बाद के 'चुनावों से ठीक पहले घोषित मुफ्त उपहारों' के बारे में उनके तीखे कटाक्ष से लगाया जा सकता है जो रिश्वत का एक ऐसा रूप है जिसे भारत में तेजी से जीवन के एक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है! ठीक वैसे ही जैसे आज के समय में भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया गया है! यहां तक कि अमरीका जैसे उन्नत लोकतंत्रों में भी कूपन या सामाजिक सुरक्षा कवर के अन्य रूपों का उपयोग किया जाता रहा है।

कॅरियर में मददगार होंगे यह पॉइंट्स

आप शिक्षा के जिस भी स्तर पर हैं, उसी अनुरूप आप अपने कॅरियर के चुनाव में विभिन्न उपायों को आजमा सकते हैं। मान लीजिये कि आप दसवीं में हैं, तो मंजिल के चुनाव के लिए आप अपने टीचर, पेरेंट्स की सहायता ले सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सा कॅरियर आपके लिए किस ढंग से लाभकारी होगा?

यह एक जांचा परखा तथ्य है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने कॅरियर के शुरुआती दौर में ही सही फैसले लेकर उचित कॅरियर का चुनाव कर लिया, तो उसकी आगे की राह काफी आसान हो जाती है। कहते हैं दुनिया में हर व्यक्ति सफर करता है, किंतु मंजिल पर पहुंचते बहुत कम लोग हैं। आप कह सकते हैं कि सही मंजिल पर कैसे पहुंचा जाए, तो इसमें यही बात समझने योग्य है कि सही मंजिल पर पहुंचने के लिए मंजिल का चुनाव, उसकी पहचान जरूरी है।

कॅरियर रुपी मंजिल का चुनाव कैसे करें?

क्या आप दसवीं में हैं? या फिर आप 12वीं में अथवा ग्रेजुएशन कर चुके हैं? आप शिक्षा के जिस भी स्तर पर हैं, उसी अनुरूप आप अपने कॅरियर के चुनाव में विभिन्न उपायों को आजमा सकते हैं। मान लीजिये कि आप दसवीं में हैं, तो मंजिल के चुनाव के लिए आप अपने टीचर, पेरेंट्स की सहायता ले सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सा कॅरियर आपके लिए किस ढंग से लाभकारी होगा? खासकर दसवीं के बाद आपको साइंस या आर्ट्स में से कोई एक स्ट्रीम चुननी होती है। इसी तरह से अगर आप 12वीं में हैं तो आप साइंस में भी मैथ्स या बायो लेकर चलना होता है अथवा आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम को लेकर पढ़ाई करना होता है। वस्तुतः यहां से कॅरियर एक दिशा ले लेता है कि आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं या फिर एनडीए अथवा दूसरे कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं। ग्रेजुएशन में तो आपकी समझ पूरी तरह से खुल चुकी होती है और आपको पूरी तरह से पता होता कि हकीकत में करना क्या है। बस कई लक्ष्यों के बीच में खुद को कंफ्यूज ना करें, क्योंकि कन्फ्यूजन आपको आपकी मंजिल से दूर कर देगा। ध्यान रखना चाहिए कि भेड़ चाल से बचना कैसे है और अपने लक्ष्य को पूरी तरह से अपने मन मस्तिष्क के अनुसार चुनना चाहिए। जब आप मंजिल को ठीक से पहचान लेते हैं तब आपका काम काफी आसान हो जाता है।

जुट जाएँ मंजिल तक पहुंचने में

जब एक बार मंजिल की पहचान हो जाती है, फिर आप तब तक ना रूकें, जब तक मंजिल पर पहुंच ना जाएँ। ध्यान रखें, डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि बैठे रहने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर अपनी मंजिल को आपने पहचान लिया है तो आपको तेजी से और मजबूत कदमों से उस और बढ़ने की आवश्यकता होती है। इसके लिए न केवल ट्रेडिशनल कोर्सेज करें, बल्कि ऑनलाइन की दुनिया से अपने आपको लगातार अपडेट करें। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आपने किसी यूनिवर्सिटी के डिग्री कोर्स में प्रवेश ले लिया है, बल्कि अपनी स्किल को निखारने के लिए आपको ऑनलाइन एजुकेशन, कोर्सेज के माध्यम से तमाम स्किल विकसित करनी होगी। इसके लिए कई फ्री तो कई पेड कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिसे आप अपनी रूचि के अनुसार चुन सकते हैं। सबसे इंपोर्टेंट है खुद को लगातार अपग्रेड करना चाहिए। हालांकि रेगुलर पढ़ाई की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता और इसके लिए आपको बेहतर से बेहतर संस्थान का चुनाव करना चाहिए और उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड को भी अपनी नजर में रखना चाहिए।

इनोवेशन को अहमियत दें

जापान के बारे में हम आप बचपन से सुनते आए हैं कि वहां बच्चे पढ़ाई के दिनों से ही प्रायोगिक चीजों में रूचि लेने लगते हैं और दसवीं तक आते आते तो घड़ी, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इत्यादि विकसित करने लगते हैं। भारत में अभी इस तरह का माहौल पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, किंतु एक सच यह भी है कि भारत में ही कई सारे छोटे बच्चे कोडिंग के माध्यम से तमाम प्रोग्राम लिखते हैं, तो कई अपनी क्रिएटिव थॉट से वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, राइटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ऐसे कई यूट्यूब चैनल आप देखते ही होंगे, जिसमें छोटे-छोटे बच्चों ने कितना कमाल किया है। तो आप भी अपने स्तर पर कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। इसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढें और हां इसका इंतजार ना करें कि अब अमुक पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी तो आप अपने कॅरियर को सेट करेंगे। इसकी बजाय पढ़ाई के कोर्सेज के दौरान ही आप खुद को स्टेबल करने की कोशिश करें। आप एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ काम करेंगे, तो भविष्य में आपके लिए यह काफी अच्छा रहेगा। आप जॉब करें या फिर अपना बिजनेस करें, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से आप खुद को सफल इंसान बनाने की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं।

भटकाव से बचें

आज के समय में तमाम एक्सपर्ट और रिसर्च इस बात के प्रति जागरूक करते हैं कि ऑनलाइन दुनिया में आपका समय बहुत खराब होता है। छोटे-छोटे बच्चे यूट्यूब और दूसरी ऑनलाइन साइट्स पर, गेम्स पर अपने जीवन का कीमती समय नष्ट करते हैं। यह धीरे-धीरे उनकी आदत बन जाती है और जो इंटरनेट अच्छी जानकारियों का सोर्स हो सकता है, उसे वह समय नुकसान करने का माध्यम बना लेते हैं। ना केवल बच्चे, बल्कि युवा भी इस पर अपना अच्छा खासा समय बर्बाद करते हैं, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के समय में समय बर्बाद करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन भी इंटरनेट ही बन गया है। इसके लिए आप अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे तो आपका कॅरियर सही दिशा में अवश्य ही आगे बढ़ेगा। पहले समय पास करने का काम नालायक दोस्त किया करते थे, लेकिन कइयों की लाइफ में अब यह स्थान इंटरनेट में ले लिया है। हालाँकि, कई लोग इंटरनेट को 'सच्चा दोस्त' बनाकर अपनी जिन्दगी में बड़े बड़े मुकाम इसी की सहायता से प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए इस के सकारात्मक पक्ष पर फोकस करें और भटकाव से बचने के लिए इंटरनेट पर पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

रिव्यू और इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है

अपनी यात्रा और अपनी अब तक की जिंदगी का रिव्यू अवश्य करें। अब तक आपने क्या किया है। अब तक कौन से अच्छे कार्य किए हैं, कौन सी छोटी गलतियां की हैं, तो कौन सी बड़ी मिस्टेक्स की हैं, इसका विचार करें। जितना अधिक आप खुद की एनालिसिस करेंगे, सार्थक दिशा में बढ़ने की संभावना भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। सच कहा जाए तो रिव्यू करना किसी परीक्षा की तरह होता है, जो एक परीक्षार्थी को बतलाता है कि उसका जीवन किस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। जैसे आज की दुनिया में किसी प्रोडक्ट का रिव्यू किया जाता है, वैसे ही खुद का रिव्यू करने से ना चूकिए। कैरियर चूज करने में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, सोशल रिलेशंस में, फैमिली रिलेशंस में आप किस ढंग से चलते हैं, इस पर सार्थक मन से अवश्य विचार करें और जो भी आपकी उलझन होती है उन उलझनों को खुद सुलझाने की कोशिश करें। अगर किसी मोड़ पर आपको लगता है कि कॅरियर चुनने में कोई गलती हुई है तो रिव्यु से वह पकड़ में आ जाएगी। पुराने गलत निर्णय को झेलने की बजाय, ठोस आधार होने पर, अपने निर्णय में समय रहते तब्दीली लाई जा सकती है।

ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बनें, जानिये इसके प्रकार भूमिकाएं और कौशल

ब्लॉकचेन तकनीक सुरक्षा को बढ़ाती है और सूचना के आदान-प्रदान को इस तरह से गति देती है जो लागत प्रभावी और अधिक पारदर्शी होता है। ब्लॉकचेन के महत्व ने विभिन्न क्षेत्रों में संगठनों का ध्यान आकर्षित किया है जिसमें बैंकिंग क्षेत्र सबसे अधिक सक्रिय है।

ब्लॉकचेन क्या होता है?

ब्लॉकचेन एक विकेन्द्रीकृत डिजिटल लेजर होता है जो दुनिया भर के हजारों कंप्यूटरों पर लेनदेन को सेव करता है। ब्लॉकचेन तकनीक सुरक्षा को बढ़ाती है और सूचना के आदान-प्रदान को इस तरह से गति देती है जो लागत प्रभावी और अधिक पारदर्शी होता है। ब्लॉकचेन के महत्व ने विभिन्न क्षेत्रों में संगठनों का ध्यान आकर्षित किया है जिसमें बैंकिंग क्षेत्र सबसे अधिक सक्रिय है। ब्लॉकचेन के परिणामस्वरूप हजारों नई नौकरी की स्थिति और मोबाइल भुगतान समाधान से लेकर स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोगों तक के नए स्टार्टअप का विकास हुआ है। वास्तव में ब्लॉकचैन आईटी दुनिया के वर्तमान परिदृश्य में शीर्ष उभरते प्रौद्योगिकी डोमेन में से एक है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का वैश्विक बाजार वर्ष 2025 तक लगभग 20 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। सैमसंग, आईबीएम, कैपजेमिनी जैसे विभिन्न आईटी जायंट हैं जो ब्लॉकचैन पेशेवरों के लिए शानदार कैरियर के अवसर प्रदान कर रही हैं और आप एक सार्थक और सफल कॅरियर बनाने के लिए ब्लॉकचेन डेवलपर बनने पर विचार कर सकते हैं।

ब्लॉकचेन डेवलपर कौन होता है?

ब्लॉकचेन डेवलपर्स वे तकनीकी पेशेवर होते हैं जो ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करते हैं और संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल को डिजाइन करना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना आदि। एक ब्लॉकचेन डेवलपर के पास ब्लॉकचेन के साथ-साथ ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर और प्रोटोकॉल के आधार पर स्मार्ट अनुबंधों को विकसित और अनुकूलित करने के लिए ज्ञान और कौशल का एक सेट होता है। वे 3डी मॉडलिंग, 3डी डिजाइन, 3डी सामग्री विकास को भी डील करते हैं जैसे कि गेम डेवलपमेंट में होता है। ब्लॉकचैन डेवलपर्स को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा जा सकता है - ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर और कोर ब्लॉकचेन डेवलपर।

ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स

ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कोर डेवलपर द्वारा योजना के अनुसार डिजाइन का विकास और कार्यान्वयन करते हैं, जैसे -

- वे डीएपी विकसित करते हैं।
- वे कोर डेवलपर्स द्वारा डिजाइन के अनुसार स्मार्ट अनुबंध लागू करते हैं।
- वे सुनिश्चित करते हैं कि डीएपी योजना के अनुसार चले।
- अन्य सेवाओं और ऐप्स के साथ ब्लॉकचेन नेटवर्क के एकीकरण पर रिसर्च और देखभाल।

कोर ब्लॉकचेन डेवलपर्स

कोर ब्लॉकचेन डेवलपर्स आर्किटेक्चर के विकास और अनुकूलन के लिए जिम्मेदार होते हैं। डेवलपर ब्लॉकचेन समाधान का समर्थन करने वाले प्रोटोकॉल को डिजाइन, विकसित और अनुकूलित करता है। एक अच्छा उदाहरण कंसेंसस प्रोटोकॉल है जो परिभाषित करता है कि ब्लॉकचेन और संसाधनों का उपयोग करने वाले सदस्य कैसे इन संसाधनों को साझा करने और उपयोग करने पर सहमत होते हैं।

- कोर ब्लॉकचेन डेवलपर्स ब्लॉकचेन की कार्यक्षमता और विशेषताओं को लागू करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे इच्छित कार्य करें।
- वे नेटवर्क की सुरक्षा को डिजाइन और कार्यान्वित करते हैं।
- वे सुनिश्चित करते हैं कि नेटवर्क चालू है।
- वे अन्य सेवाओं के साथ ब्लॉकचेन नेटवर्क के एकीकरण की योजना, डिजाइन और कार्यान्वयन करते हैं।
- वे एक ब्लॉकचेन नेटवर्क की सुविधाओं और कार्यक्षमता का विस्तार करने की योजना बनाते हैं।

आवश्यक तकनीकी कौशल

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास कंप्यूटर साइंस / इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में ऐकडेमिक बैकग्राउंड चाहिए। आप किसी विशेष स्ट्रीम में स्नातक या मास्टर डिग्री हासिल करने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए किसी विशिष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह आपको बुनियादी बातों को समझने में मदद करेगा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रभावी ढंग से सीखने के लिए आपकी फाउंडेशन रखेगा। डिग्री प्रोग्राम्स के अलावा आप विशेष तकनीक में अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकल्प चुन सकते हैं। ब्लॉकचेन प्रोफेशनल बनने का कॅरियर इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए आपको बहुत डेडिकेशन, कड़ी मेहनत और कंसिस्टेंसी की आवश्यकता होती है। लेकिन आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास को देखते हुए ब्लॉकचेन डेवलपर्स के कॅरियर का दायरा बहुत ही शानदार और उज्ज्वल होता जा रहा है।

प्रमुख स्किल्स

ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर को समझना

यह समझना सुनिश्चित करें कि ब्लॉकचेन क्या है, जैसे कि उन्नत ब्लॉकचेन सुरक्षा, ब्लॉकचेन एप्लिकेशन, ब्लॉकचेन एकीकरण और ब्लॉकचेन के फायदे और सीमाएं और साथ ही इनकी चुनौतियां। ब्लॉकचेन डेवलपर्स को ब्लॉकचेन सर्वसम्मति, हैश फंक्शन और वितरित लेजर तकनीक को समझने की आवश्यकता होती है। व्हाइट पेपर ब्लॉकचेन की वास्तुकला और कार्यप्रणाली को परिभाषित करता है। उन्हें विभिन्न ब्लॉकचेन और उनके कामकाज को समझने की जरूरत होती है जिनमें एथेरियम, बिटकॉइन, नियो और हाइपरलेगर सबसे महत्वपूर्ण हैं।

डेटा स्ट्रक्चर और डेटाबेस

एक डेवलपर को ब्लॉकचेन नेटवर्क को आवश्यकता के अनुसार उचित रूप से कॉन्फिगर करना चाहिए और इसलिए टारगेट नेटवर्क के लिए विभिन्न और इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ डेटाबेस और डेटा संरचनाओं को समझना चाहिए।

स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट

एक डेवलपर को स्मार्ट अनुबंधों के प्रकार और उन्हें विकसित करने के तरीके को समझना चाहिए।

विकेंद्रीकरण को समझना

जैसा कि ब्लॉकचेन और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों में लागू होता है। इन डीएपी को विभिन्न प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं का उपयोग करके विभिन्न ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर बनाया जा सकता है।

क्रिप्टोग्राफी को समझना

क्रिप्टोग्राफी और डिजिटल लेजर ब्लॉकचेन के कामकाज का आधार होते हैं। डेवलपर को यह समझना चाहिए कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी में लागू होने वाले एल्गोरिदम और कौन से एल्गोरिदम किस प्रकार के ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि ये एल्गोरिदम कैसे विकसित किए जाते हैं।

क्रिप्टोनॉमिक्स को समझना

यह समझना जरूरी है कि क्रिप्टोकरेंसी में ब्लॉकचेन पर कैसे कोडित किया जाता है। ब्लॉकचेन डेवलपर प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम गेम थ्योरी, मॉडलिंग क्रिप्टोनॉमिक्स के लिए गणितीय ढांचे और मॉडलिंग में शामिल मुश्किलों को सिखा सकते हैं। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि क्रिप्टोनॉमिक्स और संबंधित मौद्रिक नीतियों को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं।

कंप्यूटर कोडिंग

कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किसी भी उन्नत और प्रभावी विकेन्द्रीकृत ऐप या डीएपी के विकास के लिए आवश्यक होता है, हालांकि कुछ मामलों में आप इस कौशल के बिना शुरुआती डीएपी विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं। अधिकांश ब्लॉकचेन डेवलपर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग सीखकर इसे शुरू करते हैं और फिर ब्लॉकचेन विकास में विशेषज्ञता के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए मेनस्ट्रीम की प्रोग्रामिंग या कोडिंग भाषाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ब्लॉकचेन जैसे एरेम को एक विशिष्ट कोडिंग भाषा में ज्ञान की आवश्यकता होती है जिस पर वे कुछ भी डेवेलप करने के लिए आधारित होते हैं।

कैसे बनें वॉयस ओवरआर्टिस्ट

वॉयस-ओवर, जिसे ऑफ-कैमरा या ऑफ-स्टेज कमेंट्री के रूप में भी जाना जाता है, एक उत्पादन तकनीक है, जहां एक आवाज- जो कि कहानी का हिस्सा नहीं है- एक रेडियो, टेलीविजन उत्पादन, फिल्म निर्माण, थिएटर या फिर किसी और प्रेजेंटेशन में उपयोग किया जाता है।

क्या आपकी आवाज मधुर और प्रभावशाली है? क्या आपको अपनी आवाज से प्यार है? यदि हाँ, तो आप नि :सन्देह वॉयस-ओवर फील्ड में अपना कॅरियर आजमा सकते हैं और वॉयस-ओवर-आर्टिस्ट होकर कुछ बड़ा पैसा कमाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइये इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं।

वॉयस-ओवर क्या है?

वॉयस-ओवर, जिसे ऑफ-कैमरा या ऑफ-स्टेज कमेंट्री के रूप में भी जाना जाता है, एक उत्पादन तकनीक है, जहां एक आवाज- जो कि कहानी का हिस्सा नहीं है- एक रेडियो, टेलीविजन उत्पादन, फिल्म निर्माण, थिएटर या फिर किसी और प्रेजेंटेशन में उपयोग किया जाता है। वॉयस-ओवर प्राय : किसी मौजूदा संवाद के अलावा जोड़ा जाता है। यह पेशेवर ऑडियो के एक भाग के रूप में आवाज प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह गेमिंग, वीडियो, कार्टून, विज्ञापनों आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तकनीकी रूप से कहा जाए तो वॉइस-ओवर-आर्टिस्ट की मुख्य जिम्मेदारी लिखित शब्द को ऑडियो या वॉइस में बदलना है। इसके लिए बोलने और संवाद की कला प्रमुख है।

वॉयस-ओवर आर्टिस्ट कौन होते हैं?

हम पूरे दिन आवाजें सुनते हैं, चाहे वह मेट्रो रेल घोषणाएं हों, विज्ञापन अभियान हो या रेडियो सुन रहे हों या फिर फोन पर हेल्पलाइन पर कॉल करते समय हो। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि ये शांत और सुरीली आवाज किसकी है? वे वॉइस-ओवर-आर्टिस्ट हैं। वॉयस-ओवर कलाकार एनिमेटेड फिल्मों, वृत्तचित्रों और टेलीविजन शो के लिए आवाज प्रदान करते हैं और टेलीविजन और रेडियो विज्ञापनों में वॉयस-ओवर करते हैं। वॉयस-ओवर कलाकार एनिमेटेड पात्रों के लिए आवाजें प्रदान करते हैं, जिनमें फीचर फिल्में, टेलीविजन कार्यक्रम, एनिमेटेड लघु फिल्में और वीडियो गेम शामिल हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपने दैनिक जीवन में एक बदलाव लाने के लिए अपनी मेहनत और प्रयास इन आवाजों को दर्ज करने के लिए करते हैं। जिस डिजिटल समय में हम रहते हैं, उसमें वॉयस-ओवर कलाकारों का महत्व और प्रभुत्व बढ़ रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आजकल वॉइस-ओवर-कलाकार के रूप में कॅरियर को युवाओं के लिए एक शानदार विकल्प माना जाता है।
सामान्यतया, वॉयस-ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए अच्छी आवाज ही एकमात्र पात्रता मानदंड होता है। हालांकि, यह बहुत आसान लग सकता है, लेकिन जब यह वास्तव में एक वीडियो या एक चरित्र के लिए वॉइस-ओवर करने की बात आती है, तो कई चीजें हैं जो सामने आती हैं। लेकिन, मुख्य रूप से एक अच्छी आवाज और विभिन्न प्रकार के वॉयस मॉड्यूलेशन पर नियंत्रण वॉयस-ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। साथ ही साथ आपको भाषा और व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उच्चारण पर उचित नियंत्रण। इसके लिए आप कुछ अभिनय पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं, जहाँ से आपको एक अभिनय की डिग्री प्राप्त हो सके, क्योंकि वॉइस-ओवर काम का एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य रूप से अभिनय कार्य ही है।

वॉयस-ओवर-आर्टिस्ट बनने के लिए टॉप कॉलेज और पाठ्यक्रम

नए जमाने के कॅरियर विकल्प के रूप में, जो अब भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है, कोई स्थापित कॉलेज तो नहीं हैं जो वॉइस-ओवर-कलाकारों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में कई निजी संस्थानों ने वॉइस-कोचिंग पाठ्यक्रम पेश करना शुरू कर दिया है, जो छात्रों को मूल बातें सीखने में मदद करते हैं। उनमें से कुछ हैं :

● इंडियन वॉयस ओवर, मुंबई ● फिलमिट अकादमी, मुंबई ● वॉयस बाजार, मुंबई

इसके अलावा, कई स्थापित वॉयस-ओवर-कलाकारों ने भी इसके लिए अपने स्वयं के ट्रेनिंग क्लासेज शुरू किए हैं। आप गूगल सर्च के द्वारा अपने इलाके में ऐसे संस्थानों की पहचान कर सकते हैं।

वॉयस-ओवर-आर्टिस्ट के लिए सबसे लोकप्रिय कॅरियर

विकास क्षमता और विभिन्न पहलुओं को देखते हुए, आजकल हम देख रहे हैं कि मनोरंजन, विज्ञापन, कॉर्पोरेट, ई-लर्निंग, एनीमेशन, प्रशिक्षण, विपणन, शिक्षा, रेडियो और अन्य कार्यक्षेत्रों में आत्मविश्वास से भरी और समृद्ध आवाजों के साथ वॉयस-ओवर कलाकारों की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा, उन्नत प्रौद्योगिकी ने वीडियोगेम, ऐप, जीपीएस, टेक्स्ट टू स्पीच, इंटरनेट जैसे कई क्षेत्रों में इनकी मांग को और अधिक बढ़ा दिया है। अपेक्षाकृत अज्ञात कॅरियर विकल्प होने के बावजूद, वॉयस-ओवर-कलाकारों को दी जाने वाली भूमिकाएं और जिम्मेदारियां भिन्न भिन्न हैं। यह वीडियो के लिए बुनियादी वॉइस-ओवर गतिविधियों से शुरू होता है या रेडियो जिंगल्स के लिए आपकी आवाज की पेशकश करता है। एक बार सफल और स्थापित होने के बाद आप फिल्मों और टीवी शो या कार्टून शो के लिए डबिंग जैसे उच्च मूल्य वाले प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। एक पेशेवर कॅरियर विकल्प होने के नाते वॉयस-ओवर कलाकार बाजार में एक सम्मानजनक पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। अपेक्षाकृत नया डोमेन और एक छोटा उद्योग होने के नाते, गुणवत्ता वाले वॉयस-ओवर-कलाकारों की मांग बहुत अच्छी है और इसलिए भुगतान भी काफी अच्छा है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सपा विधायक अबू आजमी पर बरसे मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अबू आजमी के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोहिया से ज्यादा औरंगजेब समाजवादी पार्टी के आदर्श हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने वाली उनकी हालिया टिप्पणी पर विवाद के बीच महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए गए बयान परयोगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस व्यक्ति को (समाजवादी) पार्टी से निकालो और यूपी भेजो, हम उसका इलाज करेंगे। योगी ने कहा कि जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत पर शर्म महसूस करता हो, गर्व करने की बजाय औरंगजेब को अपना आदर्श मानता हो, क्या उसे हमारे देश में रहने का अधिकार है? उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप महाकुंभ को दोष देते रहते हैं।

सपा नेता अबू आजमी महाराष्ट्र विधानसभा से हुए निलंबित

मुंबई। समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अबू आजमी को मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा करने वाली उनकी विवादास्पद टिप्पणी के बाद बजट सत्र तक महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। इससे एक दिन पहले महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उन्होंने आजमी को सदन से निलंबित करने की मांग रखी है। शिंदे ने संवाददाताओं से कहा कि हमने उनके बयान की निंदा करते हैं। उनके बयान की उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी और महाराष्ट्र के लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा; हमने उन्हें (सदन से) निलंबित करने की अपनी मांग रखी है। सदन में अबू आजमी के खिलाफ महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने प्रस्ताव पेश किया था। सदन ने प्रस्ताव पारित कर दिया। हाल ही में मरीन ड्राइव इलाके में मीडिया से बातचीत के दौरान आजमी ने कहा कि औरंगजेब एक अच्छे प्रशासक थे।

यमुना नदी में शुरू हो चुका है रिवरफ्रंट बनाने का काम : प्रवेश

नईदिल्ली। दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार को नाव से यमुना का निरीक्षण किया और कहा कि पिछले 10 दिनों में नदी से 1,300 टन कचरा हटाया गया है। हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक यमुना की सफाई थी। उन्होंने कहा कि हम मौजूदा एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) की क्षमता बढ़ाएंगे और नए स्थापित करेंगे ताकि यमुना में आने वाले कचरे को उससे पहले ही उपचारित किया जा सके। औद्योगिक क्षेत्रों में नए एसटीपी लगाए जाएंगे। अगर कोई शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि हम यह काम दो साल के भीतर पूरा कर देंगे। यमुना रिवरफ्रंट का विकास पहले ही शुरू हो चुका है। सभी स्थलों की पहचान कर ली गई है, और कोई भी अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि वे नदी में कूड़ा न फेंकें।

कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार को दिया अल्टीमेटम

रांची। झारखंड विधानसभा सत्र के सातवें दिन सदन में सत्ता पक्ष के एक विधायक ने अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बुधवार को जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के विधायक प्रदीप यादव ने स्वर्णरेखा परियोजना में हुई गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मामले के आरोपी कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सरकार से सवाल पूछा। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव का कहना था कि विभाग ने केवल अपर डिविजन क्लर्क संतोष कुमार के विरुद्ध केवल क्यों कार्रवाई की ? जबकि इस गड़बड़ी में कई लोग शामिल थे। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि इस मामले की उचित कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में वह धरने पर बैठेंगे। सदन में विधायक प्रदीप यादव कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर के विरुद्ध एफआईआर और उचित कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। उन्होंने भरी सदन में मांग पूरी नहीं होने की स्थिति धरने पर बैठने की बात कह डाली।

मायावती ने भतीजे के बाद भाई आनंद कुमार पर की कार्रवाई

लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद अब उनके पिता आनंद कुमार को भी नेशनल कोआर्डिनेटर पद से हटा दिया है। उनकी जगह रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोआर्डिनेटर बनाया गया है। मायावती ने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि काफी लम्बे समय से निस्वार्थ सेवा व समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनन्द कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में नेशनल कोआर्डिनेटर भी बनाया गया था, उन्होंने पार्टी व मूवमेन्ट के हित के मद्देनजर एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका स्वागत है। मायावती ने लिखा कि ऐसे में आनंद कुमार पहले की ही तरह बीएसपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मेरे दिशा-निर्देशन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। अब उनकी जगह यूपी के जिला सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोआर्डिनेटर की नई जिम्मेदारी दी गई है।

कांग्रेस विधायक के बयान से बिहार महागठबंधन में घमासान

■ राहुल-सोनिया तय करेंगे तेजस्वी का मुख्यमंत्री पद!

पटना। बिहार चुनाव 2025 की तैयारी के बीच महागठबंधन में सिरफुटौव्वल शुरू होता दिख रहा है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बयान दिया है कि तेजस्वी यादव तभी मुख्यमंत्री बनेंगे जब राजद को अधिक सीट आएगी। उसके बाद दिल्ली आलाकमान इसपर फैसला लेगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे यह तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा।

भागलपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि आगामी बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन की जीत होगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या नहीं, इसपर अजीत शर्मा ने कहा कि वो निश्चित बनेंगे। उनकी पार्टी अगर सबसे अधिक सीट जीतेगी तो वो जरूर

मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन यह सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे तय करेंगे।

कांग्रेस विधायक पर राजद का पलटवार

अजीत शर्मा के इस बयान से राजद खेमे में नाराजगी दिखी। एक न्यूज चैनल पर बात करते हुए राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अजीत शर्मा के बयान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का निर्णय उनके नेता करेंगे लेकिन बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अजीत शर्मा के बयान को हल्के में लेते हुए राजद प्रवक्ता ने कहा- 'ऐसा तो नहीं है कि सदन के उनके नेता या पार्टी अध्यक्ष ऐसा कुछ बोले हैं। अजीत शर्मा कौन होते हैं यह तय करने वाले। वो अपनी विधानसभा देखेंगे। वो बस विधायक हैं। उनकी बातों को कितना महत्व देंगे। पार्टी के नेता पहले ही बोल दिए हैं।'

भाजपा ने ली महागठबंधन की चुटकी

वहीं राजद और कांग्रेस की उठापटक पर भाजपा ने भी चुटकी ली है। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस विवाद पर कहा कि राजद और कांग्रेस मिलकर भी 25-30 सीट से अधिक नहीं जीत सकेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। राजद को अजीत शर्मा के बयान पर जवाब जरूर देना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि ये लोग जब जेल जाने की बारी आती है तब ही एक होते हैं।

भगदड़ में जान बचाने वालों की आवाज नहीं सुनी जा रही: राहुल

नई दिल्ली। राहुल गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से हुई मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के दौरान कुलियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। वे आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। हम उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे।

अपने यूट्यूब चैनल पर कुलियों से बातचीत का वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां कुली भाइयों से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे सभी ने मिलकर भगदड़ वाले दिन लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। राहुल गांधी ने कहा कि चाहे लोगों को भीड़ से निकालने की बात हो या घायलों को एंबुलेंस और प्रशासन तक पहुंचाना हो। मृतकों के शवों को बाहर निकालने के लिए शारीरिक क्षमता,

ठेले का उपयोग करना हो या अपनी जेब से पैसा खर्च करना हो, उन्होंने हर तरह से यात्रियों की मदद की।

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि मैं दिहाड़ी मजदूरी करने आने वाले इन भाइयों की संवेदना देखकर प्रभावित हूं। वे वित्तीय कठिनाइयों में जी रहे हैं, लेकिन उनमें जोश और सद्भावना की कमी नहीं है। उन्हें मदद की जरूरत है। उन्होंने अपनी मांगें बताई हैं। मैं निश्चित रूप से उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करूंगा।

एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस नेता ने एक कुली के हवाले से कहा कि किसी-किसी दिन खाने के भी पैसे नहीं होते। हर घर पर पैसे भेजें या खाना खाएं। हमारे कुली भाई ऐसी ही कठिनाइयों में जीने को मजबूर हैं। मैं उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखूंगा और हम अधिकारों के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। राहुल गांधी ने रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के दौरान लोगों की जान बचाने और राहत कार्य में मदद करने के लिए कुलियों का धन्यवाद किया। वीडियो में कुली गांधी से कह रहे हैं कि उनकी मांग है कि उन्हें ग्रुप डी की नौकरी मिले।

15 फरवरी को मची थी भगदड़

15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले लोगों की भारी भीड़ थी साथ ही अन्य यात्री भी थे। दो ट्रेनों के लेट होने के चलते भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई।

केजरीवाल के वीआईपी काफिला पर आप ने दी सफाई

नईदिल्ली। राज्यसभा में अपने संभावित प्रवेश को लेकर चल रही चर्चा के बीच, आम आदमी पार्टी (आप) के अरविंद केजरीवाल इस समय 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए पंजाब में हैं। हालाँकि, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की उनके विशाल काफिले के लिए आलोचना की गई, आप सांसद स्वाति मालीवाल ने व्यंग्यात्मक कटाक्ष करते हुए कहा कि काफिला डोनाल्ड ट्रम्प के काफिले से भी बड़ा था। केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता होशियारपुर के पास धम्म धजा विपश्यना केंद्र में बुधवार से शुरू होने वाले ध्यान पाठ्यक्रम में भाग लिया। भाजपा और कांग्रेस ने भी केजरीवाल के काफिले को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

हालांकि, इसको लेकर अब आप की सफाई आ गई है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर खतरे की आशंका के चलते गृह मंत्रालय की ओर से उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। बीजेपी को गंदी राजनीति छोड़नी चाहिए और अपना ध्यान दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को गाली देने से कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल न तो पंजाब से राज्यसभा जा रहे हैं और न ही पंजाब के सीएम बन रहे हैं। बीजेपी को अफवाह फैलाने से दूर रहना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने

पूछा, पंजाब के करदाताओं द्वारा वित्त पोषित एक भव्य सुरक्षा परेड की किस तरह की विपश्यना की आवश्यकता है? उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, जो कभी वैगनआर में एक आम आदमी होने का दिखावा करते थे, अब बुलेटप्रुफ लैंड क्रूजर, 100 से अधिक पंजाब पुलिस कमांडो, जैमर और एम्बुलेंस के एक भव्य काफिले में एक वीआईपी महाराजा की तरह विपश्यना के लिए जा रहे हैं, जो शांति के लिए एक रिट्रीट है। उन्होंने कहा कि यदि सत्ता ही उनकी परीक्षा थी, तो वे बुरी तरह विफल रहे हैं.... आप का सच सामने आ गया है, धोखा, पाखंड और वीआईपी अहंकार चरम पर है। भाजपा दिल्ली ने एक्स पर लिखा कि क्या से क्या हो गए देखते-देखते। दिल्लीवासियों ने भ्रष्ट केजरीवाल को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, फिर भी उनके मन से सत्ता का मोह कम होने का नाम नहीं ले रहा। खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल अब सत्ता में भी नहीं हैं, फिर किस हक से गाड़ियों के इतने बड़े काफिले के साथ पंजाब में वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं? यह कैसा आम आदमी है जिसके शौक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे?

इस बीच, 5 फरवरी के दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल और भाजपा के प्रवेश वर्मा के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आप प्रमुख पर आडंबरपूर्ण और भव्य जीवन शैली के आदी होने का आरोप लगाया।

स्लम इलाकों के लोगों से मिलेंगी दिल्ली सीएम रेखा

नईदिल्ली। बजट को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सरकार लगातार लोगों से राय ले रही है। इसी कड़ी में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं स्लम इलाकों में जाकर बहनों और परिवारों से मिलूंगी, इस सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में उनसे बात करूंगी। युवाओं और अलग-अलग सेक्टर के प्रोफेशनल्स से चर्चा की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली का बजट लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगा। हमने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए हैं, उन्हें पूरा करेंगे, चाहे वह सभी महिलाओं को रुपये देने की योजना हो या सिलेंडर।

सीएम ने साफ तौर पर कहा कि किसी को हमें यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि हमारा एजेंडा चलेगा, उनका (आप) नहीं। दिल्ली सरकार 24 से 26 मार्च के बीच विधानसभा में 2025-26 के लिए 'विकसित दिल्ली' बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, ''इसे जनता का बजट बनाने के लिए हम पांच मार्च को विधानसभा परिसर में विभिन्न महिला संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। इसके अलावा, हम छह मार्च को शिक्षा क्षेत्र के हितधारकों और व्यापारियों के साथ चर्चा करेंगे।''

उन्होंने एक ईमेल आईडी और एक व्हाट्सऐप नंबर भी साझा किया, जहां दिल्ली के निवासी बजट के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। गुप्ता ने दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 'संकल्प पत्र' में किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा और उनकी सरकार इस दिशा में युद्ध स्तर पर काम कर रही है। गुप्ता ने कहा कि विधानसभा में अब तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की केवल दो रिपोर्ट पेश की गई हैं और उनमें पहले ही पिछली आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ कई भ्रष्टाचार के आरोप उजागर हो चुके हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

इंडिया से हार के बाद स्टीव स्मिथ ने लिया वनडे से सन्यास

नईदिल्ली। चैम्पियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में भारत से मिली हार के बाद आस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान और मुख्य बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने बुधवार को एक दिवसीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया । पैंतीस बरस के स्मिथ ने मैच में 96 गेंद में 73 रन बनाये। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने एक बयान में कहा कि स्मिथ ने अपने साथी खिलाड़ियों को भारत से चार विकेट से मिली हार के बाद अपने फैसले से अवगत करा दिया था। वह टी20 और टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे ।

स्मिथ ने कहा ,'' मुझे लगता है कि यह दूसरों के लिये रास्ता बनाने का सही समय है। यह शानदार सफर रहा और मैंने हर पल का मजा लिया।'' उन्होंने कहा ,'' टेस्ट क्रिकेट प्राथमिकता है और मैं विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल को लेकर उत्साहित हूं । इसके बाद वेस्टइंडीज और इंग्लैंड से खेलना है । मुझे लगता है कि अभी भी योगदान दे सकता हूं ।''

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, स्मिथ टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे। उनका ये फैसला शायद लॉस एंजिल्स में 2028 ओलंपिक खेलों का हिस्सा बनने की इच्छा को दर्शाता है। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में हार के बाद अपने फैसले के बारे में स्टीव स्मिथ ने टीम के साथियों को बताया और कहा कि ऐसा लगता है कि अब खेल छोड़ने का सही समय है। वहीं एक प्रेस रिलीज में स्मिथ ने कहा कि, ये बेहतरीन सफर रहा है और मैंने इसके हर मिनट का आनंद लिया है। बहुत सारे अद्भुत पल और बेहतरीन यादें रही है। दो वर्ल्ड कप जीतना एक शानदार उपलब्धि थी, साथ ही कई शानदार साथियों ने इस यात्रा को साझा किया। अब लोगों के लिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करने का एक बेहतरीन मौका है, इसलिए ऐसा लगता है कि अब खेल छोड़ने का सही समय है। टेस्ट क्रिकेट अभी भी प्राथमिकता है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

निफ्टी 22,337 पर बंद हुआ सेंसेक्स 740 अंक चढ़ा

नईदिल्ली। एशिआई बाजारों में तेजी के रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार बुधवार (5 मार्च) को पॉजिटिव नोट पर ओपन हुए। इंडेक्स में हैवी वेटेज रखने वाले आईटी स्टॉक्स में उछाल ने भी बाजार को ऊपर खींचा है। अमेरिकी के कॉमर्स मिनिस्टर ने कनाडा और मैक्सिको टैरिफ पर कुछ राहत का संकेत दिया है। इससे सेंटीमेंट पर सकारातमक असर पड़ा है। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज मामूली बढ़त लेकर 73,005.37 पर खुला। जबकि मंगलवार को यह 72,989 के स्तर पर बंद हुआ था। दोपहर 1:20 बजे सेंसेक्स 810.76 अंक या 1.11% चढ़कर 73,800 पर चल रहा था। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 भी बढ़त में खुला। दोपहर 1:20 बजे निफ्टी 271.65 अंक या 1.23% की बढ़त लेकर 22,354.30 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। ब्रोडर मार्केट्स में भी आज बढ़त देखने को मिली।

2 अप्रैल से भारत पर लगेगा टैरिफ : राष्ट्रपति ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी संसद में अपना भाषण दिए। अपनी सरकार की खूबिया गिनाते हुए ट्रंप ने कई अहम बातें कही है। वहीं, अपनी टैरिफ नीति को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, अन्य देशों ने दशकों से हमारे खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल किया है और अब हमारी बारी है कि हम उन अन्य देशों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करना शुरू करें। ट्रंप ने कहा, भारत हमसे 100% ऑटो टैरिफ वसूलता है, यह प्रणाली अमेरिका के लिए उचित नहीं है, यह कभी नहीं थी, 2 अप्रैल को, पारस्परिक टैरिफ लागू होते हैं और वे हम पर, अन्य देशों पर जो भी टैरिफ लगाते हैं, हम उन पर टैरिफ लगाएंगे...वे हम पर जो भी कर लगाते हैं, हम उन पर कर लगाएंगे।

दिग्गज डिफेंस कंपनी ने 150% डिविडेंड का किया ऐलान

नईदिल्ली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने अपने निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा दिया है। कंपनी ने बुधवार (5 मार्च) को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.50 रुपये प्रति शेयर यानी 150% का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया। अंतरिम डिविडेंड का भुगतान घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने डिविडेंड के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए 5 मार्च 2025 को बॉर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की बैठक बुलाई थी। बैठक में एलिजिबल शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बुधवार (5 मार्च) को रेगुलटरी फाईलिंग में कहा, 25 फरवरी, 2025 के हमारे पहले लेटर के क्रम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 5 मार्च, 2025 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 1 रुपये के फुली पेड अप हर शेयर पर 1.50 रुपये की दर से अंतरिम डिविडेंड दिया जाएगा।

भारत के सर्विस सेक्टर में दिखी तेजी

नईदिल्ली। फरवरी में भारत के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ तेज रही और इसका परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) बढ़कर 59 पर पहुंच गया। जनवरी में यह 56.5 था, जो बीते दो साल से ज्यादा का सबसे निचला स्तर था। एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई की यह रिपोर्ट बुधवार को जारी की गई, जिसे एसएंडपी ग्लोबल ने तैयार किया है। हालांकि, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुस्ती देखने को मिली। नए ऑर्डर्स में गिरावट और उत्पादन की धीमी रफ्तार के चलते फरवरी का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 14 महीने के निचले स्तर 56.3 पर आ गया। जनवरी में यह 57.7 था। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ के चलते कंपोजिट पीएमआई भी बढ़कर 58.8 हो गया, जो जनवरी में 57.7 था। भारत के सेवा क्षेत्र में फरवरी 2025 में तेजी देखी गई है।

महंगाई की मार और मरम्मत का अधिकार

विवेक एस अग्रवाल

उपभोक्तावादी युग में गौण होते उपभोक्ताओं पर कुछ सबसे बड़ी मार नित्य नई प्रकट होती यांत्रिक उपकरणों और संसाधनों से पड़ रही है। बीते वर्षों में पुरजोर तरीके से मरम्मत के अधिकार की बात विभिन्न स्तरों पर उठाई गई, लेकिन इस बाबत सरकार द्वारा एक पोर्टल की स्थापना तथा उसकी संपूर्ण संरचना के लिए कमेटी गठित करने से आगे कदम नहीं बढ़ पाए।

वर्तमान युग में, जहां हर वस्तु त्वरित बदलाव के सांचे में ढल रही है, वहीं निर्माताओं की भी अपेक्षा रहती है कि मॉडल में बदलाव या उन्नयन के नाम पर उपभोक्ता उसके नए उत्पाद को खरीदते रहें। इससे निर्माता का स्वार्थ तो सध जाता है, पर उपभोक्ता आर्थिक मायाजाल में फंस जाता है। जब मरम्मत के अधिकार संबंधी चर्चाएं चल रही थीं, तो उसमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और कृषि उपकरणों को ही तरजीह दी गई, जबकि आमजन को प्रभावित करने वाले मेडिकल उपकरणों और मशीनरी को इस चर्चा से बाहर ही रखा गया। यह अलग बात है कि अभी सम्मिलित उपकरण व मशीनरी भी अपनी पूर्णता हासिल नहीं कर पाई। प्रचार-प्रसार के अभाव में उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा विकसित 'राइट टू रिपेयर' पोर्टल भी आमजन के चलन में नहीं आया है।

मरम्मत के अधिकार के बिना निर्माता के एकाधिकार के चंगुल में उपभोक्ता कहीं मशीन या उपकरण स्वयं क्रय करके फंस रहा है, तो मेडिकल जैसे क्षेत्र में निदान एवं उपचार हेतु मशीनों एवं उपकरण के बढ़ते उपयोग के कारण अनचाहे भी एकाधिकार वाली व्यवस्था का भार ढोता है। इसका एक पहलू यह भी है कि प्रथमतया तो संबंधित

मशीनों के कलपुर्जे कहीं उपलब्ध ही नहीं होते और यदि हो भी जाएं, तो दूसरे से मरम्मत कराने पर उनसे जुड़ी हुई गारंटी-वारंटी भी समाप्त हो जाती है। यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि मशीन की बाहर मरम्मत का दंड भी क्रेता अस्पताल या निदान केंद्र को परोक्ष तौर पर चुकाना ही पड़ता है। यह ऐसा गंभीर विषय है, जिस पर न सिर्फ व्यापक चर्चा होनी चाहिए, बल्कि कानून के जरिये चिकित्सकीय उपकरणों को भी अन्यत्र मरम्मत के अधिकार के दायरे में लाया जाना चाहिए।

विडंबना यह है कि हर निर्माता नवीनता के नाम पर आंशिक, क्षणिक एवं कलात्मक बदलाव कर निरंतर नए उत्पाद को बाजार में ले आता है और आधुनिकतम इलाज के नाम पर उसे स्वीकार करना और अपनाना इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के लिए जरूरी हो जाता है। अन्यथा, वे स्वयं को बाजार की दौड़ से पीछे पाने लगते हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान में 3 टेस्ला एमआरआइ मशीन का प्रचलन है, जो 15 से 20 करोड़ रुपये की लागत की होती है और निर्माता कंपनी उसके रखरखाव हेतु लगभग 50 लाख रुपये प्रतिवर्ष का 10 वर्ष के लिए अनुबंध करती है। लेकिन इस बीच में ही इसके आंशिक उन्नयन का नया मॉडल आ जाता है और बाजार की दौड़ में रहने के लिए संस्थान को उसे खरीदना पड़ता है।

मरीज की भी अपेक्षा रहती है कि उसका निदान एवं उपचार आधुनिकतम मशीन से ही हो। वर्तमान युग में शनैः शनैः मरम्मत का स्थान परिवर्तन या नवीनता ने ले ली है। निर्माता नए मशीन-उपकरण को बाजार में लाने के साथ-साथ अपने ही पुराने उत्पाद को अप्रचलित करार देने लगता है तथा उसके कल पुर्जों को भी चलन से बाहर बता देता है। नतीजतन, चिकित्सकीय संस्थान कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए लंबी प्रतीक्षा के बजाय बदलाव करना पसंद करते हैं और पुरानी मशीन को कबाड़ में डाल देते हैं। यह न तो पर्यावरण सम्मत है और न ही मरीज के हित में, क्योंकि नई मशीन की लागत इलाज और निदान पर अतिरिक्त बोझ के रूप में दिखती है। इससे अनजान मरीज आधुनिकतम निदान एवं इलाज की प्रत्याशा में बढ़े हुए खर्च को चुपचाप सहन करता है। बीमित व्यक्ति के लिए तो यह प्रत्यक्ष बोझ नहीं होता, पर सामान्य लोग इसकी चपेट में आए बिना भी नहीं रहते।

सदन में गरमाया बीपीएल फर्जी राशन कार्ड का मुद्दा

रायपुर । विधानसभा में बुधवार को बीपीएल के फर्जी राशन कार्ड का मामला जोर-शोर से उठा। सत्ता पक्ष के भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल पर सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 57 एपीएल कार्डधारकों को बीपीएल में बदल दिया गया है, जिनके हितग्राही बंगला और कार के मालिक हैं।

फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा

विधायक शुक्ला ने सदन में बताया कि वर्ष 2022 से 2025 के बीच यह हेरफेर किया गया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के एक

अधिकारी की आईडी का उपयोग कर मध्यप्रदेश के सागर से ये कार्ड जारी किए गए, जबकि संबंधित परिवारों ने इसके लिए आवेदन तक नहीं किया था। उन्होंने इस पूरे मामले में दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

मंत्री का इनकार, विधायक की चुनौती

खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने सदन में ऐसे किसी भी फर्जी राशन कार्ड के बनाए जाने से इंकार कर दिया। इस पर विधायक सुशांत शुक्ला ने दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने की चुनौती दी और अपनी उपस्थिति में पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की।

विभागीय मंत्री ने जांच की घोषणा की

विधानसभा में इस मुद्दे पर काफी देर तक बहस चली, जिसके बाद अंततः मंत्री दयाल दास बघेल ने मामले की जांच कराने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की घोषणा की। अब देखना होगा कि सरकार इस बड़े फर्जीवाड़े पर कितनी सख्ती से कदम उठाती है।

भावना बोहरा ने विधानसभा में उठाया जनसंपर्क विभाग में अनियमितता का मुद्दा

रायपुर । विधानसभा सत्र के दौरान पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने जनसंपर्क विभाग में विज्ञापन के लिए आवंटित राशि में अनियमितता, शिक्षकों के रिक्त पद, आदिवासी भूमि विक्रय और इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी से जुड़े मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाया।

विधायक बोहरा ने जनसंपर्क विभाग द्वारा सरकारी विज्ञापनों के आवंटन में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए। सरकार ने जानकारी दी कि 243 डिजिटल समाचार पोर्टल इम्पेनल हैं, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय समाचार पोर्टल इम्पेनल नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3179 डिजिटल पोर्टल विज्ञापन पर 67.16 करोड़, 12,881 समाचार पत्र विज्ञापन पर 147.36 करोड़, 901 टीवी चैनल विज्ञापन पर 140.93 करोड़ और 187 रेडियो विज्ञापन पर 5.29 करोड़ खर्च किए गए।

भावना बोहरा ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष की तुलना में विज्ञापन खर्च दोगुना किया गया, जो सरकारी धन का दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि होर्डिंग्स के लिए तीन महीने का अनुबंध होने के बावजूद एक माह में ही हटाए जाने और पूरे भुगतान किए जाने की शिकायतें मिली हैं। इस पर मंत्री ने जांच कराने का आश्वासन दिया। विधायक भावना बोहरा ने कबीरधाम जिले में अनुसूचित जनजातियों की भूमि बिक्री अनुमति से जुड़े प्रश्न किए। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने लिखित उत्तर में बताया कि 2021-22 से 2024-25 तक कुल 118 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से मात्र 16 को अनुमति दी गई। वहीं, बिना न्यायालय की अनुमति से किसी भी भूमि की बिक्री नहीं की गई है।

सदन में गूंजा भारतमाला प्रोजेक्ट का मुद्दा, विपक्ष ने सरकार को घेरा...

रायपुर । विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में भारतमाला प्रोजेक्ट का मुद्दा गूंजा। विपक्ष के विधायकों ने सवाल दागते हुए सरकार को जमकर घेरा। वहीं इस दौरान मामले में स्पीकर डॉ रमन सिंह ने कहा- अगले सप्ताह भारतमाला प्रोजेक्ट के विषय पर चर्चा होगी। साथ ही नसीहत देते हुए कहा कि, गंभीरता से सदन में प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए जाएं। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा- मुझे आज सुबह 10.30 बजे जवाब दिया गया। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- यह परंपरा उचित नहीं, इसलिए व्यवस्था आनी चाहिए। प्रश्नकाल के पहले जवाब मिलने पर आसंदी ने नाराजगी जताते हुए संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा- प्रश्नों के जवाब पूरी गंभीरता से सदन में दिए जाएं। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने केज कल्चर के लिए अनुदान में अनियमितता का मामला सदन में उठाया। इस संबंध में सीएम के स्थान पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि, 19 लाख रुपए के गबन पर जांच की जा रही है। शिकायत के 3 दिन बाद जांच शुरू की गई। वहीं इस दौरान सत्तापक्ष के सदस्यों ने भी जांच पर आपत्ति जताई है।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- दोषी व्यक्ति को रिटायर होने का मौका दिया गया। धर्मजीत सिंह ने भी दोषी पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाते हुए कहा- दोषी अधिकारी ने पत्नी के नाम पर लाभ लिया, 19 लाख रुपए पत्नी के नाम से गबन किया गया। मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने जांच की घोषणा करते हुए कहा कि, अगर जांच में सिद्ध होगा तो वसूली करेंगे। इस पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सदन में तीखी बहस हो गई। विपक्षी सदस्यों ने दोषी को बचाने का आरोप लगाया।

राजधानी में यातायात सुधार को लेकर बृजमोहन ने ली उच्च स्तरीय बैठक

रायपुर । राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने, सड़कों के चौड़ीकरण तथा अन्य आवश्यक बुनियादी सुधारों को लेकर रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर निगम विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

बैठक में सांसद अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सड़कों की वर्तमान स्थिति एवं संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। वीआईपी चौक और रिंग रोड पर लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सर्विस रोड को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही, कमल विहार समेत अन्य आवश्यक स्थानों पर ग्रेट सेप्रेटर के निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारियों को योजना तैयार करने के लिए कहा। सांसद अग्रवाल ने राजधानी में चार से अधिक ओवरब्रिज तथा कचना

सहित विभिन्न क्षेत्रों में पांच से अधिक अंडरपास निर्माण पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही रायपुर - बलौदा बाजार - सारंगढ़ रोड की स्थिति को लेकर भी समीक्षा की और इसके उन्नयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ वीआईपी रोड की सर्विस लेन को भी जगह जगह खोलने के निर्देश दिए हैं। सांसद अग्रवाल ने राजधानीवासियों को ट्रैफिक जाम और पार्किंग समस्याओं से राहत दिलाने के लिए एक समग्र कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से लंबित कार्यों की जानकारी मांगी और आश्वस्त किया कि वे इन मुद्दों को आगामी लोकसभा सत्र के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के समक्ष उठाएंगे। इसके अलावा, स्वीकृत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि राजधानी को आधुनिक और सुगम यातायात प्रणाली से युक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बैठक में प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई दिग्विजय सिंह, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी के भतपैहरी, कार्यपालन अभियंता राजीव नशीने, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त निदेशक विनीत नायर, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशाषी अभियंता एस एस मांझी, कार्यपालन अभियंता गोविंद अहिरवार, नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष तोमर मिले केंद्रीय मंत्री डॉ. माण्डविया से

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से दिल्ली में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान श्री तोमर ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में तथा खेल मंत्री टंकराम वर्मा के मार्गदर्शन में चल रहे युवा आयोग के कार्यों से उन्हें अवगत कराया।

युवा आयोग के अध्यक्ष श्री तोमर ने केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे अभियानों में छत्तीसगढ़ की भी भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित करने आग्रह भी किया। डॉ. मांडविया ने फिट इंडिया, खेलो इंडिया अभियानों में छत्तीसगढ़ की सहभागिता सुनिश्चित करने का भरोसा दिया तथा माई भारत पोर्टल में 3.30 लाख रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ से होने पर बधाई भी दी।

केंद्रीय मंत्री ने आगामी यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के युवाओं की ज्यादा-से-ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। श्री तोमर ने यह विश्वास दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉ. मांडविया के नेतृत्व में चलाए जा रहे समस्त कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ के युवा बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे और विकसित भारत की ओर हम सब आगे बढ़ेंगे। श्री तोमर ने केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया से छत्तीसगढ़ के लिए स्टेडियम, मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने हेतु भेजे गए प्रस्तावों से उन्हें अवगत कराया, जिस पर उन्होंने यथाशीघ्र स्वीकृति देने की सहमति प्रदान की।

प्लेसमेंट कर्मचारी कल्याण संघ नगर निगम रायपुर के पदाधिकारी मिले महापौर मीनल से

रायपुर। रायपुर की नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती मीनल चौबे से मिलकर प्लेसमेंट कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष श्री संजय एड़े सहित पदाधिकारियों ने बुके प्रदत्त करते हुए प्रथम नागरिक महापौर पद का कार्यभार ग्रहण करने पर हार्दिक शुभकामनायें दीं।

अध्यक्ष ने संघ की प्रमुख मांगों के संबंध में अवगत कराते हुए प्लेसमेंट कर्मचारियों को नगर निगम से सीधा वेतन भुगतान करने, 4000 रू. श्रम सम्मान निधि प्रदान करने सहित अन्य प्रमुख मांगो के संबंध में महापौर से चर्चा की गई। जिस पर महापौर श्रीमती चैबे ने संघ की मांगो को पूरा करवाने के प्रति आश्वस्त किया। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारी पवन चवरगुवाल, देवेन्द्र साहू, गिरधारी साहू, मनीष तिवारी, गुलषन ताम्रकार, हेमंत फरिकार, रवि साहू, भोला साहू, ललित साहू, शबाना बेगम, नीलू शर्मा, रीता राव, शकुन हरपाल, संजना हरपाल, सावित्री उपस्थित थे।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मिलित होंगी महापौर मीनल

रायपुर नगर पालिक निगम अधिकारी कर्मचारी एकता संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 7 मार्च को नगर निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के चतुर्थ तल पर स्थित निगम सामान्य सभा सभागार में महिला दिवस पर दोपहर ढाई बजे से आयोजित कार्यक्रम में राजधानी शहर की प्रथम नागरिक और नगर निगम रायपुर की नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती मीनल चौबे सम्मिलित होंगी। वे कार्यक्रम में रायपुर नगर पालिक निगम अधिकारी कर्मचारी एकता संघ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नगर निगम रायपुर की महिला कर्मचारियों को सम्मानित करेंगी।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

सेक्स सीडी कांड मामले में भूपेश बघेल बरी

रायपुर । छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सेक्स सीडी कांड मामले में बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है और उन पर लगाई गई सभी धाराएं हटा दी गई हैं। इस फैसले के बाद भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सत्यमेव जयते। सेक्स सीडी कांड का मामला पहली बार अक्टूबर 2017 में सामने आया था। इसमें दावा किया गया था कि वीडियो में तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत शामिल हैं। इस मामले में रायपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार की साजिश बताया था।सितंबर 2018 में इस मामले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर साजिश रचने का आरोप लगा था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जमानत लेने से इनकार कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए थे।2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिला और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने।

कल्पना योगेश तिवारी बेमेतरा जिला पंचायत अध्यक्ष बनी

रायपुर। दुर्ग बेमेतरा कोरिया व कांकेर में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा समर्थित अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। दुर्ग से सरस्वती बंजारे निर्विरोध निर्वाचित हुई है। बेमेतरा में भाजपा समर्थित .कल्पना योगेश तिवारी जिला अध्यक्ष बनी हैं उन्हे 10 वोट मिले जबकि कांग्रेस के शशि गायकवाड़ को मात्र चार वोट मिले। लंबे अरसे बाद भाजपा का बेमेतरा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर

कब्जा हुआ है। कोरिया से मोहित राम पैकरा अध्यक्ष बने हैं। कांकेर से तारा ठाकु

दुर्ग में जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। यहां भाजपा समर्थित सरस्वती बंजारे निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। दुर्ग जिला पंचायत में भाजपा समर्थित प्रत्याशी ज्यादा संख्या में जीतकर आए थे। इससे परे बेमेतरा में भाजपा ने कल्पना योगेश तिवारी को जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी घोषित किया था। कल्पना प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतकर आई हैं। कांग्रेस ने शशि गायकवाड़ को अध्यक्ष प्रत्याशी बनाया। कल्पना योगेश तिवारी को 10, और शशि को 4 वोट ही मिल पाए। लंबे समय बाद बेमेतरा में भाजपा का जिला पंचायत पर कब्जा हुआ है। वहां भाजपा में खुशी की लहर है।

मोहम्मद बख्श ने कांग्रेस के इशारे पर आदिवासी समाज का किया अपमानः ठाकुर

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने बलरामपुर में विजयी जनपद सदस्य मोहम्मद बख्श द्वारा अपनी विजय रैली के दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम और स्थानीय विधायक के खिलाफ की गई आपत्तिजनक व अश्लील टिप्पणियों की कड़ी निंदा कर इसे सम्पूर्ण

हिन्दू समाज के अंगभूत घटक जनजातीय समाज के अपमान की कांग्रेस-पोषित सोची-समझी कुत्सित मानसिकता का परिचायक बताया है। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के लोगों का राजनीतिक डीएनए एक-सा है। चुनावी जीत पर अहंकार उनके सिर चढ़कर बोलने लगता है और चुनावी हार पर वे बौखलाहट का प्रदर्शन करने लगते हैं। ठाकुर ने कड़े शब्दों में कांग्रेसियों को चेतावनी दी है कि चुनावी जीत-हार के बाद कांग्रेस के लोग अपना मानसिक और भाषायी संतुलन खोकर अपनी बदमिजाजी, बदहवासी और बदजुबानी का प्रदर्शन करने से बाज आ जाएँ। कांग्रेसी यह कतई न भूलें कि छत्तीसगढ़ में अब सनातनी संस्कृति के ध्वजवाहक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार है और उसमें इस तरह की बदजुबानी और बदमिजाजी की किसी को कोई इजाजत नहीं है।

चेम्बर चुनाव-2025 - प्रारंभिक मतदाता सूची का किया गया प्रकाशन

रायपुर। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव 2025 का बुधवार शाम 5 बजे चेम्बर कार्यालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी शिवराज भंसाली के हस्ताक्षर से प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। प्रदेश के 27480 मतदाताओं की मतदाता सूची का प्रकाशन के समय निर्वाचन अधिकारी रमेश गांधी, बालकृष्ण दानी, के.सी. माहेश्वरी, महावीर तालेड़ा, अनिल कुचेरिया, संजय देशमुख, अमित वर्मा, चुनाव नियंत्रक एच.एस.कर, चुनाव कार्यालय प्रभारी एस.एम. रावते, सह प्रभारी शशिकांत गुप्ता उपस्थित थे।

उक्त आशय की जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी प्रकाश गोलछा ने बताया कि प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया प्रदेश के सभी मतदाताओं की सुविधा हेतु चेम्बर www.cgchamber.org वेबसाइट पर जिले के समस्त मतदाता ओपन कर देख सकते हैं। प्रकाशित मतदाता सूची का अवलोकन चेम्बर कार्यालय में समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक कर सकते हैं किसी भी मतदाता को उसमें त्रुटि सुधार हेतु आवेदन दिनांक 6 मार्च गुरुवार से 8 मार्च शनिवार तक प्रातः 11 से दोपहर 2 बजे तक लिखित में आवेदन देना होगा7अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 10 मार्च 2025 शाम 5 बजे किया जावेगा। इसी अनुसार मतदाताओं को मताधिकार प्राप्त होगा।

छग गृह निर्माण मंडल ने किया वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 का शुभारंभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में सभी के लिए आवास योजना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ. पी. चौधरी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 की शुरुआत की है, जिसके तहत घर खरीदने वालों को 10 से 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।इस योजना को 20 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसे तत्काल शुरू नहीं किया जा सका। अब 01 मार्च से इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है, जिससे आम जनता को किफायती दरों पर घर खरीदने का सुनहरा अवसर मिला है।छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष एवं आवास विभाग के सचिव अंकित आनंद ने बताया कि यह योजना हर वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें घरों की कीमतों पर 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।मंडल आयुक्त कुंदन कुमार ने बताया कि बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। इच्छुक लाभार्थी मंडल की वेबसाइट www.cghb.gov.in पर लॉग-इन करके अपने सपनों का घर बुक कर सकते हैं।

महिला मड़ई का शुभारंभ, मंत्री राजवाड़े ने किया स्टॉलों का अवलोकन

रायपुर । महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने मंगलवार को रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय महिला मड़ई का शुभारंभ किया। 'सशक्त महिला समृद्ध महिला' की थीम पर इस मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। यह मड़ई आगामी 8 मार्च तक चलेगा। इस मड़ई में प्रदेश भर की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की प्रदर्शनी एवं विक्रय किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिला मड़ई में महिला समूहों द्वारा बिक्री सह प्रदर्शनी के लिए लगाए स्टालों का अवलोकन किया। महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मंत्री श्रीमती राजवाड़े को अपने बीच पाकर उत्साहित हुई। श्रीमती राजवाड़े ने यहां लगे विभिन्न स्टालों में जमकर खरीदारी की और

रागी,सत्तू और बाजरे का लड्डू स्वाद चखा और उसकी सराहना भी की। इस अवसर पर मंत्री राजवाड़े ने जागेश्वर यादव का सम्मान किया।इस अवसर पर विधायक सुनील सोनी, सदस्य राज्य महिला आयोग श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, शालिनी राजपूत शाहिद, सचिव श्रीमती सम्मी आबिदी, संचालक जन्मेजय महोबे सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। महिला मड़ई में लगाए गए 87 स्टॉलों बिक्री-सह प्रदर्शनी का अवलोकन दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है। मड़ई में सेल्फी जोन बनाया गया है जो आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए प्ले जोन भी बनाया गया है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए आकर्षक झूले एवं खेल-खिलौने की व्यवस्था की गई है।महिला मड़ई में नवा बिहान, महतारी वंदन सखी सेंटर, वुमन हेल्पलाइन, दिशा दर्शन, कन्या विवाह, स्पॉन्सरशिप, फास्टर केयर, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड,चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल विवाह, दत्तक ग्रहण और आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का स्टॉल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। इस मड़ई मेले में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच की गरिमा दिवाकर ने मनमोहक प्रस्तुति दी। मड़ई मेले में महिला एवं बाल विकास विभाग के समूहों के साथ अन्य विभागों के समूह जैसे-एनआरएलएम, वन विभाग, पंचायत विभाग इत्यादि की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विक्रय एवं प्रदर्शन के लिए निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रदेश के पांच विश्वविद्यालयों में छत्तीसगढ़ी भाषा की हो रही पढ़ाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ की दो सरकारी और तीन प्राइवेट विश्वविद्यालयों में छत्तीसगढ़ी भाषा में पोस्ट ग्रैजुएट की पढ़ाई कराई जा रही हैं। पिछले पांच साल में 219 विद्यार्थियों ने एमए छत्तीसगढ़ी की उपाधि प्राप्त कर ली है। छत्तीसगढ़ी भाषा में मास्टर डिग्री प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को रोजगार देने हेतु सरकार की कोई योजना नहीं है और ना ही सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है। ऐसी जानकारी उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री ने विधानसभा में लिखित रुप से दी है।

कांग्रेस विधायक अनिला भेडिया ने विधानसभा में प्रश्न पूछा था। उन्होंने पूछा था कि प्रदेश के किन-किन विश्वविद्यालयों में छत्तीसगढ़ी भाषा के माध्यम से एम.ए. (पी.जी.) कोर्स का संचालन कब से किया जा रहा है? संचालित विश्वविद्यालयों में वर्ष 2020 से जनवरी, 2025 की स्थिति में कितने विद्यार्थियों ने एम.ए. की उपाधि प्राप्त की है? छत्तीसगढ़ी भाषा में मास्टर डिग्री प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को रोजगार/नौकरी देने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या योजना बनाई गई तथा कितने डिग्रीधारी को नौकरी प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश के 02 राजकीय विश्वविद्यालय (1) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (संचालन वर्ष 2013-14) (2) कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर (संचालन वर्ष 2022-23) तथा 03 निजी विश्वविद्यालय (1) डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर (संचालन वर्ष 2018-19) (2) आईएसबीएम. विश्वविद्यालय, गरियाबंद (संचालन वर्ष 2017-18) (3) भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग (संचालन वर्ष 2024-25) में एमए छत्तीसगढ़ी की पढ़ाई हो रही है और उन्हें कोर्स संचालन हेतु मान्यता दी गई है। वर्ष 2020 से जनवरी 2025 की स्थिति में कुल 219 विद्यार्थियों को एम.एम. (छत्तीसगढ़ी) की उपाधि दी गयी है। छत्तीसगढ़ी भाषा में मास्टर डिग्री प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को रोजगार/ नौकरी देने हेतु सरकार की कोई योजना नहीं है। डिग्रीधारी नौकरी पाने वाले विद्यार्थी की संख्या की जानकारी का संधारण भी नहीं किया जाता है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.